Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-16, अंक-24 16-31 दिसंबर, 2021 (पाक्षिक) ₹20

जब 'डबल इंजन' की सरकार होती है, तो डबल तेजी से काम भी होता है

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश प्रवास

'भाजपा लोकतंत्र को अपने मूल सिद्धांतों में से एक मानती है'

त्रिपुरा निकाय चुनावों में भाजपा की शानदार जीत | भारतीय राष्ट्र का मूल स्वरूप | मोदी—एक करिश्माई संगठनकर्ता

इंफाल (मणिपुर) में संविधान दिवस पर बाबासाहब बी.आर. अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में वनटांगिया समुदाय की एक सभा को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

तिरुपुर (तमिलनाडु) में नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ 'मां शाकुंभरी' विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

जयपुर (राजस्थान) में 'जनप्रतिनिधि संकल्प महासम्मेलन' के दौरान केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का स्वागत करते राजस्थान भाजपा के कार्यकर्तागण

जौनपुर (उत्तर प्रदेश) में काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 ## 'गलत जगह बटन दब जाए तो जिन्ना याद आता है लेकिन सही जगह बटन दबे तो राष्ट्र सर्वोपरि होता है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 22 नवंबर 2021 को गोरखपुर में पूर्वांचल क्षेत्र के 12 जिलों के लगभग 28 हजार बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद किया और उनसे आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर घर-घर...

09 ### जब 'डबल इंजन' की सरकार होती है, तो डबल तेजी से काम भी होता है: नरेन्द्र मोदी

गत सात दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास...

10 ### जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चार दिसंबर को देहरादून (उत्तराखंड) में लगभग 18,000 करोड़ रुपये की...

11 ### 'राजनीति के अपराधीकरण को भाजपा की एन. बीरेन सरकार ने ख़त्म किया है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 26 नवंबर 2021...

23 ### आज उत्तर प्रदेश में क़ानून का राज है: अमित शाह

गत दो दिसंबर को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय...

विशेष
भारतीय राष्ट्र का मूल स्वरूप / अटल बिहारी वाजपेयी 18

श्रद्धांजलि
हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोगों का असामयिक निधन 19

साक्षात्कार
प्रधानमंत्री मोदीजी अनुसूचित जनजाति समाज के उत्थान को लेकर अंतर्मन से काम कर रहे हैं : समीर उरांव 24

लेख
मोदी–एक करिश्माई संगठनकर्ता / तरूण चुग 26

'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम / राम प्रसाद त्रिपाठी 28

'पीएम-कुसुम' किसानों की आय दोगुनी व कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायक / विकास आनंद 29

'मन की बात'
हमारे स्वास्थ्यकर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से पेश की एक नई मिसाल 33

अन्य
'भाजपा तमिल गौरव, तमिल संस्कृति और दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल के साथ खड़ी है' 13

त्रिपुरा निकाय चुनाव में भाजपा की शानदार जीत 14

नवंबर, 2021 में दूसरा सबसे अधिक जीएसटी संग्रह, 1.31 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा 15

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

आज सरकार इस बात का इंतजार नहीं करती कि नागरिक उसके पास अपनी समस्या लेकर आएंगे, तब वो कोई कदम उठाएगी। अब सरकार ऐसी है, जो सीधे नागरिकों तक जाती है।

जगत प्रकाश नड्डा

चाहे पार्टी हो या सरकार, हमारा एक ही उद्देश्य रहता है। हम सबको साथ लें, सबके प्रयास को जोड़ें, सबके विकास के बारे में सोचें और सबका विश्वास लेकर चलें। हम सभी को इस मूल मंत्र को लेकर चलना है।

अमित शाह

कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है और अपनी संस्कृति को प्रोत्साहित कर सकता है, जब वह सुरक्षित हो। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लिए सीमा सुरक्षा का मतलब ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले सभी जवानों पर पूरे देश को गर्व है।

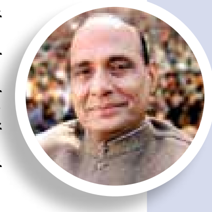

राजनाथ सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पी.एम. गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च, 2022 तक बढ़ाने का बेहद सराहनीय निर्णय लिया गया है। ग़रीबों के हित में लिए गए इस निर्णय से देश के 80 करोड़ ग़रीबों का कल्याण होगा। प्रधानमंत्रीजी का आभार!

बी.एल. संतोष

हिमाचल प्रदेश अपनी पात्र वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की दो खुराक देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वास्तव में यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। श्री जयराम ठाकुर, स्वास्थ्यकर्मियों और सभी सामाजिक संगठन को बधाई।

नितिन गडकरी

भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। संविधान दिवस के अवसर पर देश को प्रगतिशील संविधान देने वाले बाबासाहेब अंबेडकर जी और सभी देशभक्तों को नमन। सभी को भारतीय संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय कानून दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

'कमल संदेश' परिवार

की ओर से

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी

को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि।

शत शत नमन!

जन्मदिन : 25 दिसंबर

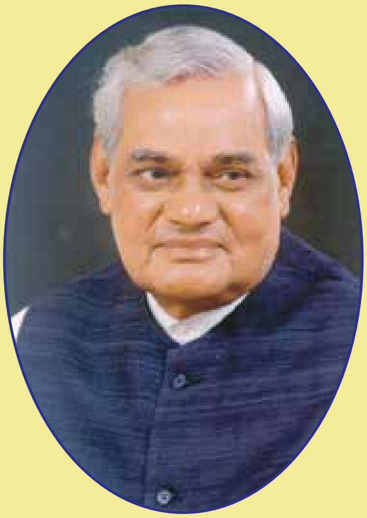

संपादकीय

भारत की एकजुट शक्ति का सम्मान

आज जब देश के 85 प्रतिशत पात्र लोगों को कोविड-19 टीके की प्रथम खुराक मिल चुकी है तथा 50 प्रतिशत लोगों का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है, पूरा विश्व भारत की सराहना कर रहा है। अब जबकि देश में 130 करोड़ से भी अधिक टीके लग चुके हैं और कई रिकॉर्ड देश के नाम दर्ज हो चुके हैं, वैश्विक महामारी के विरुद्ध युद्ध में भारत एक अग्रणी देश के रूप में सामने आया है। विश्व के सबसे विशाल, तेज एवं पूर्णतः निःशुल्क टीकाकरण अभियान में एक दिन में कई बार एक करोड़ टीके का आंकड़ा पार कर तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर एक ही दिन में 2.5 करोड़ टीके का आंकड़ा पार कर देश ने उन्हें एक विशेष उपहार दिया। इसमें सबसे अद्भुत उपलब्धि यह रही कि ये रिकॉर्ड देश में 'मेड इन इंडिया' टीकों के बल पर प्राप्त किया तथा सभी को निःशुल्क टीके उपलब्ध कराकर अपनी क्षमता का परिचय दिया। भारत के वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, उद्यमियों एवं फार्मा क्षेत्र, जिन्होंने रिकॉर्ड समय में टीकों का निर्माण किया, की क्षमता पर देश के अटूट विश्वास का यह प्रतिफल है। आज ये 'मेड इन इंडिया' टीके न केवल भारत के लिए बल्कि विश्वभर की मानवता के लिए वरदान साबित हुए हैं।

मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाकर एक बार पुनः 80 करोड़ लोगों को मार्च, 2022 तक निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ध्यान देने योग्य है कि इसे कोविड-19 वैश्विक महामारी में 80 करोड़ जनता लॉकडाउन के कारण चुनौतियों का सामना कर रही थी, उन्हें निःशुल्क राशन उपलब्ध कराकर भारी राहत देने के लिए शुरू किया गया था। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ एवं करिश्माई नेतृत्व में देश ने न केवल हर चुनौती को अवसर में बदला, बल्कि गरीब, किसान, प्रवासी मजदूर, महिला, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक एवं समाज के कमजोर वर्गों को भारी राहत दी। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अंतर्गत अनेक राहत देने वाले पहलों के कारण पूरे देश में महामारी का सामना करने का आत्मविश्वास जाग्रत हुआ। इस दौर में देश के चिकित्सकों, नर्सों, चिकित्साकर्मियों, लैब तकनीशियनों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मियों एवं कोरोना योद्धाओं; जिन्होंने निःस्वार्थ सेवा के नए प्रतिमान गढ़े; उन्होंने अपने समर्पण से भारत का मस्तक ऊंचा किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज जब देश इस वैश्विक महामारी से बाहर निकलने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रहा है, इन प्रयासों का प्रभाव अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। आज, सकल घरेलू उत्पाद में उत्साहजनक उछाल देखा जा सकता है। जिससे सभी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भारतीय अर्थव्यवस्था के भारी छलांग की भविष्यवाणी कर रही हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है कि महामारी के दौर में भी अनेक परियोजनाएं अपने तय समय से पूर्व ही अपना कार्यपूर्ण करने में सफल हुई हैं। साथ ही, भारत अपनी पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने में भी सफल हुआ है।

> **कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दल टीकों के विरुद्ध दुष्प्रचार कर हर प्रकार की बाधा उत्पन्न कर रहे थे, वहीं पूरे राष्ट्र ने रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ टीके का लक्ष्य प्राप्त कर सभी विरोधियों को निरुत्तर कर दिया**

देश एक 'नए भारत' की राह पर अग्रसर है जो 'वसुधैव कुटुंबकम्' के सिद्धांतों को साकार करते हुए 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के लिए कृतसंकल्पित है। वैश्विक महामारी के दौर में भी भारत हर देश के साथ खड़ा रहा तथा हर संभव सहायता की। भारत प्रत्येक जरूरतमंद देश का मित्र साबित हुआ है। एक ओर जहां देश के अंदर ही कुछ लोग भारत जैसे विशाल देश में टीकाकरण अभियान के सफलतापूर्वक चलने पर प्रश्नचिह्न लगा रहे थे और कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दल टीकों के विरुद्ध दुष्प्रचार कर हर प्रकार की बाधा उत्पन्न कर रहे थे, वहीं पूरे राष्ट्र ने रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ टीके का लक्ष्य प्राप्त कर सभी विरोधियों को निरुत्तर कर दिया। आज भारत देश के हर पात्र नागरिक को टीके की कम से कम एक खुराक देने के करीब है, पूरा विश्व भारत की एकजुट शक्ति का सम्मान कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत की एकजुटता हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकती है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

बूथ अध्यक्षों से संवाद, उत्तर प्रदेश

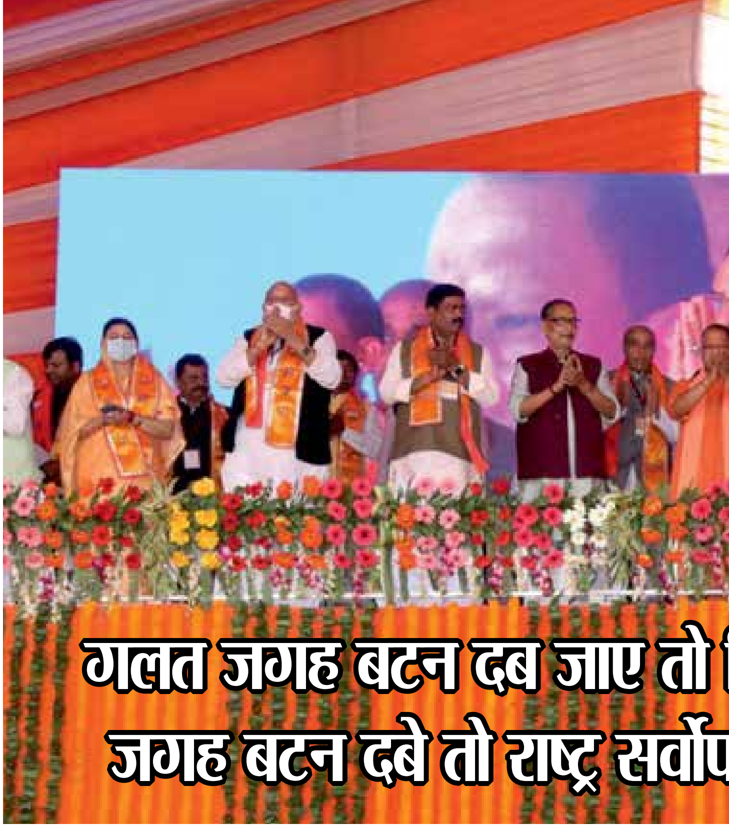

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 22 नवंबर, 2021 को गोरखपुर में पूर्वांचल क्षेत्र के 12 जिलों के लगभग 28 हजार बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद किया और उनसे आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर घर-घर जाकर विपक्ष के दुष्प्रचार और झूठी राजनीति की पोल खोलने का आह्वान करते हुए केंद्र में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार और प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों को रखने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश के भाजपा प्रभारी श्री राधा मोहन सिंह, प्रदेश के महामंत्री (संगठन) श्री सुनील बंसल, सह प्रभारी श्री अरविंद मेनन, श्री विवेक ठाकुर, केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी, गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन सहित राज्य सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायक, क्षेत्र के सांसद, प्रदेश और क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश की महान धरा को शत-शत नमन करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी है जहां बूथ अध्यक्ष सम्मेलन भी विशाल जनसभा का रूप ले लेती है। हर तरफ केसरिया ही केसरिया नजर आता है। केसरिया सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला रंग है। आप सब यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि आप उस पार्टी के सदस्य हैं जिसके नेता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व देश और प्रदेश के विकास एवं कल्याण के लिए अर्पित कर दिया है। ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की पूंजी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है।

> हमें प्रजातंत्र पर विश्वास है लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस सहित विपक्ष को परिवारतंत्र में विश्वास है, वहां केवल एक परिवार ही पनप सकता है

श्री नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में जब बाकी सभी राजनीतिक दल आइसोलेशन में चले गए थे, दूर-दूर तक जनता के दुःख-दर्द को बांटने वाला कोई न था, तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी थी जिसके कार्यकर्ता अपने प्राणों की चिंता किये बगैर जन-जन के कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे। यह केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र है जहां साधारण से साधारण परिवार से आने वाला कार्यकर्ता भी देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर सकता है और मुझ जैसा एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आप ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि आप बूथ अध्यक्षों में से कोई एक प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और मुख्यमंत्री भी।

भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियों के बीच की कार्य-संस्कृति को तुलनात्मक रूप से स्पष्ट करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि हमें प्रजातंत्र पर विश्वास है लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस सहित विपक्ष को परिवारतंत्र में विश्वास है, वहां केवल एक

जिन्ना याद आता है लेकिन सही
रि होता है : जगत प्रकाश नड्डा

परिवार ही पनप सकता है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में आस्था रखते हैं तो वे वंशवाद में। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है तो उनके लिए एक परिवार का वंश सर्वोपरि है। हम 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की राजनीति करते हैं, वे वोट बैंक और वर्ग विशेष के तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। हम अंत्योदय के लिए कार्य करते हैं, वे एक परिवार के उदय के लिए कार्य करते हैं। पहले तो चाचा के लिए भी करते थे लेकिन अब तो चाचा को भी छोड़ दिया है।

विपक्ष की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए श्री नड्डा ने कहा कि हम तो महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल तक और देश के पुनर्निर्माण में योगदान देने वाले देश के वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों का सदैव स्मरण करते रहते हैं, लेकिन क्या कारण है कि जब-जब चुनाव आते हैं तो विपक्ष को पाकिस्तान और जिन्ना याद आ जाता है? उन्हें जनता को बताना चाहिए कि आजादी के इतने साल बाद भी राष्ट्रीय योद्धाओं और देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले महान मनीषियों का स्मरण करने के बजाय उन्हें संकीर्ण मानसिकता वाले लोग, देश को बांटने वाले लोग और आतंक का पनाहगाह क्यों याद आते हैं? ऐसे लोगों को इतिहास भी कभी माफ़ नहीं करेगा। ये पाकिस्तान और जिन्ना का नाम लेकर राजनीति क्यों करते हैं, इसके लिए हमें गहराई में जाने की जरूरत है। मैं सभी बूथ अध्यक्षों से निवेदन करता हूं कि आप प्रदेश के घर-घर में ये संदेश पहुंचाएं कि जिन्ना और पाकिस्तान का नाम जपने वालों को, देश के खिलाफ काम करने वालों का नाम जपने वालों को घर बिठाइये और भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाइये।

श्री नड्डा ने कहा कि मैं प्रदेश की जनता का आह्वान करते हुए कहना चाहता हूं कि गलत जगह बटन दब जाए तो जिन्ना याद आता है लेकिन सही जगह बटन दबे तो राष्ट्र सर्वोपरि होता है।

बूथ अध्यक्षों से संवाद, कानपुर (उत्तर प्रदेश)

'हम राष्ट्रवाद के अग्रदूत हैं, वे परिवारवाद के अनुयायी हैं'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 23 नवंबर, 2021 को निराला नगर मैदान, कानपुर में कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के लगभग 22 हजार बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद किया और उन्हें आगामी उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के संदर्भ में दिशानिर्देश दिए। इस सम्मेलन में सेक्टर समन्वयक सहित हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश के भाजपा प्रभारी श्री राधा मोहन सिंह, उप-मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, अन्नपूर्णा देवी, श्री भानु प्रताप वर्मा, प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री सुनील बंसल, श्री सत्यदेव पचौरी सहित राज्य सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायक, क्षेत्र के सांसद, प्रदेश और क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।

विपक्ष पर हमला करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि बाकी सभी पार्टियां एक ही तंत्र में विश्वास रखती हैं, वह है परिवारतंत्र। उन्हें केवल एक परिवार विशेष की चिंता है, सगे-संबंधियों की चर्चा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी शिखर तक पहुंच सकता है। हम राष्ट्रवाद के अग्रदूत हैं, वे परिवारवाद के अनुयायी हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जन-जन के कल्याण के लिए समर्पित हैं, उन्हें केवल वोटबैंक की राजनीति ही रास आती है, जाति और वर्ग विशेष की राजनीति से वे बाहर ही नहीं निकल पाते।

श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आजादी के 70 सालों से बार-बार हम एक नारा लगाते थे– एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेगा लेकिन इस नारे को साकार किया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और गृह मंत्री श्री अमित शाह की कुशल रणनीति ने। वर्षों बाद करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को भी ट्रिपल तलाक के दंश से आजादी मिली। हमने भगवान् श्रीराम की

कानपुर क्षेत्रीय भाजपा कार्यालय का उद्घाटन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 23 नवंबर, 2021 को अपने उत्तर प्रदेश प्रवास के दूसरे और अंतिम दिन साकेत नगर, कानपुर में कानपुर क्षेत्रीय भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ-साथ 7 जिला कार्यालयों का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा प्रभारी श्री राधा मोहन सिंह, उप-मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य, प्रदेश महामंत्री संगठन श्री सुनील बंसल, क्षेत्र के सभी सांसद, जिलाध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी सहित कई विधायक और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। इससे पहले उन्होंने कानपुर के सब्जी मंडी, किदवई नगर स्थित बाबा नामदेव गुरुद्वारा में मत्था टेका और अरदास की। यहां उन्होंने सिख समुदाय के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किये गए कार्यों पर विस्तार से चर्चा की।

कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन और 7 जिला कार्यालयों पीलीभीत, प्रतापगढ़, गोंडा, ग्रेटर नोएडा, हमीरपुर, कानपुर दक्षिण और कानपुर देहात के कार्यालयों के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि हमने शून्य से शिखर तक की यात्रा परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले अपने कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और बलिदान के बल पर ही की है। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुरुआत में दुकान पर बैठकर, घरों में बैठकर, किराए के मकान में बैठकर पार्टी का कार्य किया और विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। ऐसे पार्टी कार्यकर्ता ही कार्यालय की नींव के पत्थर हैं।

इससे पहले बाबा नामदेव गुरुद्वारा में अरदास के बाद श्री नड्डा ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सिख समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए जितना कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। सिख समुदाय की पुरानी मांगों को प्रधानमंत्रीजी ने पूरा किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं जिन्होंने 1984 के दंगों में शामिल लोगों को एसआईटी बैठाकर जेल भेजने का काम किया है, भले ही वह कितने ही प्रभावशाली क्यों न हों।

जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने का जो संकल्प लिया था कि रामलला हम आयेंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे- वह संकल्प भी प्रधानमंत्रीजी ने शिलान्यास कर पूरा कर दिया।

श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों ने किसानों को लंबे समय तक गुमराह करने का पाप किया है। किसानों का भला केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। कांग्रेस को तो केवल एक ही काम करना आता है- चुनाव आए नहीं कि किसानों की कर्जमाफी के झूठे वादे का खेल शुरू हो जाता है। सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने 10 वर्षों में केवल एक बार किसानों का कर्जा माफ किया, वह भी केवल लगभग 57 हजार करोड़ रुपये, इसमें भी कुछ ही किसानों के कर्ज माफी हुए और इसमें भी घोटाले की खबर आई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केवल तीन सालों में ही 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक एकाउंट में केवल किसान सम्मान निधि योजना में ही 1.53 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंचा दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 2.54 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। करोड़ों लोगों को स्वामित्व कार्ड और स्वायल हेल्थ कार्ड दिया गया है। नीम कोटेड यूरिया के यूरिया की कालाबाजारी रुकी है। साथ ही, डीएपी पर प्रति बोरी 1200 रुपये की सब्सिडी मोदी सरकार दे रही है।

श्री नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास का फर्क पड़ा भी है और दिखता भी है। आजादी के 70 सालों में उत्तर प्रदेश में केवल 4 मेडिकल कॉलेज बने जबकि डबल इंजन की सरकार में अब तक 30 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और जल्द ही ये संख्या 42 तक पहुंच जाएगी। कानपुर में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बन रहा है तो लखनऊ में कैंसर संस्थान बनाया गया है। लाखों महिलाओं को आवास योजना में अपने घर का मालिकाना हक़ मिला है तो प्रदेश को कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी सौगात मिली है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है तो जेवर एयरपोर्ट का काम भी शुरू होने जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का काम शुरू है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे भी विकास के नए द्वार खोल रहा है। काशी विश्वनाथ और विन्ध्याचल कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर- डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है। बुंदेलखंड में 2,185 करोड़ रुपये की लागत से जल जीवन मिशन का कार्य शुरू हुआ है। आवास योजना के तहत 4 लाख घर बुंदेलखंड क्षेत्र में दे दिए गए हैं। कानपुर और झांसी को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है।

श्री नड्डा ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश से माफिया और गुंडों के डर से पलायन होता था, आज माफिया और गुंडों का पलायन हो रहा है। सपा सरकार में उत्तर प्रदेश में माफिया राज और गुंडा राज का आतंक था, आज दूर-दूर तक न तो माफिया है और न गुंडा। खनन माफिया भी बिल में दुबके हुए हैं। महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में डकैती के केस में 70 प्रतिशत की कमी आई है, लूट के मामले 65 प्रतिशत कम हुए हैं, अपहरण की घटनाएं 50 प्रतिशत घटी हैं, बलात्कार के मामले 33 प्रतिशत कम हुए हैं और हत्या के मामलों में भी लगभग 25 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है– ये अपने आप बताता है कि उत्तर प्रदेश में कानून-राज लाने का यदि किसी ने कार्य किया है तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। ■

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण

जब 'डबल इंजन' की सरकार होती है, तो डबल तेजी से काम भी होता है: नरेन्द्र मोदी

गत सात दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने एम्स और उर्वरक संयंत्र के उद्घाटन तथा गोरखपुर में आईसीएमआर के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के नए भवन के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई दी। उन्होंने 5 साल पहले एम्स और उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखने को याद किया तथा आज दोनों का उद्घाटन करते हुए एक बार शुरू की गई परियोजनाओं को पूरा करने की सरकार की कार्यशैली को रेखांकित किया।

श्री मोदी ने कहा कि जब 'डबल इंजन' की सरकार होती है, तो विकास कार्यों के क्रियान्वयन की गति भी दोगुनी हो जाती है। उन्होंने कहा कि जब नेक नीयत से काम होता है, तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पातीं। जब गरीब-शोषित-वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है; तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी लाकर दिखाती है। उन्होंने कहा कि आज का समारोह इस बात का प्रमाण है कि जब 'न्यू इंडिया' तय कर लेता है तो कुछ भी असंभव नहीं है।

> **जब नेक नीयत से काम होता है, तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पातीं। जब गरीब-शोषित-वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है; तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी लाकर दिखाती है**

श्री मोदी ने कहा कि त्रिस्तरीय दृष्टिकोण के तहत सरकार ने यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग की शुरुआत करके यूरिया के दुरुपयोग को रोका। उन्होंने कहा कि करोड़ों किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए गए हैं, ताकि वे यह तय कर सकें कि उनके खेत के लिए किस तरह की खाद या उर्वरक की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यूरिया का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों को भी फिर से खोलना पड़ा। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में 5 उर्वरक संयंत्रों का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से देशभर में 60 लाख टन यूरिया उपलब्ध हो जाएगा।

श्री मोदी ने हाल के वर्षों में गन्ना किसानों के हित में किए गए अभूतपूर्व कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की। उन्होंने गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को हाल ही में 300 रुपये तक बढ़ाने और पिछली सरकारों द्वारा विगत 10 वर्षों में गन्ना किसानों को किए गए भुगतान के लगभग बराबर भुगतान करने के लिए सरकार की सराहना की।

श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद इस सदी की शुरुआत तक देशभर में केवल एक ही एम्स था। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 और एम्स को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि पिछले सात साल में 16 नए एम्स खोलने के लिए देश भर में निर्माण कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज अवश्य हो।

श्री मोदी ने कहा कि सब जानते थे कि इस क्षेत्र के किसानों के लिए और यहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट कितना जरूरी था। उन्होंने कहा कि इस प्लांट का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इसे फिर से शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।

श्री मोदी ने कहा कि आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर घर में अन्न पहुंचाने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि इसका लाभ उत्तर प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को मिल रहा है। हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को होली से आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर उत्तर प्रदेश का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में हैं और निवेशक दिल खोलकर उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। यही 'डबल इंजन का डबल विकास' है। उन्होंने कहा कि इसलिए डबल इंजन की सरकार पर उत्तर प्रदेश को विश्वास है। ■

जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं: नरेन्द्र मोदी

हमारे पहाड़, हमारी संस्कृति, आस्था के गढ़ तो हैं ही, ये हमारे देश की सुरक्षा के किले भी हैं। पहाड़ों में रहने वालों का जीवन सुगम बनाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चार दिसंबर को देहरादून (उत्तराखंड) में लगभग 18,000 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इसमें दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक), दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कॉरिडोर से हलगोआ, सहारनपुर से भद्राबाद, हरिद्वार को जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड एलाइनमेंट परियोजना, हरिद्वार रिंग रोड परियोजना, देहरादून-पांवटा साहिब (हिमाचल प्रदेश) सड़क परियोजना, नजीबाबाद-कोटद्वार सड़क चौड़ीकरण परियोजना और लक्ष्मण झूला के पास गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण शामिल है। उन्होंने चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट, देहरादून, देहरादून में जलापूर्ति, सड़क तथा जल निकासी प्रणाली के विकास, श्री बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री-यमुनोत्री धाम में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्यों और हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी।

श्री मोदी ने सात परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का लक्ष्य इस क्षेत्र में यात्रा को सुगम बनाना है। क्षेत्र में भूस्खलन की समस्या का समाधान, देवप्रयाग से श्रीकोट तक और एनएच-58 पर ब्रह्मपुरी से कोडियाला तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना, यमुना नदी पर निर्मित 120 मेगावाट की व्यासी जलविद्युत परियोजना, देहरादून में हिमालयी संस्कृति केंद्र और देहरादून में अत्याधुनिक इत्र तथा सुगंध प्रयोगशाला (सुगंधित पौधों के लिए केंद्र) इनमें शामिल हैं।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस शताब्दी की शुरुआत में अटल जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था।

> साल 2007 से 2014 के बीच जो केंद्र की सरकार थी, उसने सात साल में उत्तराखंड में केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए, जबकि हमारी सरकार ने अपने सात साल में उत्तराखंड में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे का निर्माण किया है

श्री मोदी ने कहा कि लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही, जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दोगुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। बदली हुई कार्यशैली के बारे में श्री मोदी ने कहा कि आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति 'गतिशक्ति' की है, दोगुनी-तीन गुनी तेजी से काम करने की है।

श्री मोदी ने कनेक्टिविटी के लाभों का जिक्र करते हुए कहा कि केदारनाथ त्रासदी से पहले 2012 में 5 लाख 70 हजार लोगों ने दर्शन किए थे। उस समय यह एक रिकॉर्ड था, जबकि कोरोना काल शुरू होने से पहले 2019 में 10 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि यानी केदार धाम के पुनर्निर्माण ने न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई, बल्कि वहां के लोगों को रोजगार-स्वरोजगार के भी अनेक अवसर उपलब्ध कराए हैं।

विकास की गति की तुलना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2007 से 2014 के बीच जो केंद्र की सरकार थी, उसने सात साल में उत्तराखंड में केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए, जबकि हमारी सरकार ने अपने सात साल में उत्तराखंड में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे का निर्माण किया है।

उन्होंने कहा कि हमारे पहाड़, हमारी संस्कृति, आस्था के गढ़ तो हैं ही, ये हमारे देश की सुरक्षा के किले भी हैं। पहाड़ों में रहने वालों का जीवन सुगम बनाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

प्रधानमंत्री ने एक सुंदर कविता के साथ अपनी बात समाप्त की, जिनकी प्रमुख चार पंक्तियां निम्न हैं:

"जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं;
जहां ऊंचे-नीचे सब रस्ते, बस भक्ति के सुर में गाते हैं।
उस देव भूमि के ध्यान से ही, मैं सदा धन्य हो जाता हूं;
है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं।।" ■

'राजनीति के अपराधीकरण को भाजपा की एन. बीरेन सरकार ने ख़त्म किया है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 26 नवंबर, 2021 को मणिपुर के ओइनाम (बिष्णुपुर जिला, मणिपुर) में 'गो टू विलेज 2.0 कार्यक्रम और खोंगजोम में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और मणिपुर की जनता से राज्य के विकास के लिए एक बार पुनः भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। इससे पहले उन्होंने इम्फाल में संविधान गौरव दिवस अभियान का शुभारंभ किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया।

खोंगजोम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में मणिपुर में सालों बंदी और और रोड ब्लोकेड चलता था। अब वह ख़त्म हो गया है। राजनीति के अपराधीकरण को भाजपा की एन. बीरेन सरकार ने ख़त्म किया है।

श्री नड्डा ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी मणिपुर में 2.70 लाख घर ऐसे थे, जहां शौचालय नहीं थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर में 2.60 लाख शौचालय बनवाकर महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। 'गो टू विलेज' कार्यक्रम में लगभग 1.56 लाख गैस कनेक्शन दिए गए। यहां लाखों लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना से जोड़ा गया है। 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत भारत सरकार ने देश के लगभग 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज दिया है और मणिपुर की भाजपा सरकार ने अलग से अपने नागरिकों को दो लाख रुपये का कवरेज दिया है।

श्री नड्डा ने कहा कि मणिपुर में पीएम आवास योजना में 88 हजार पक्के मकान दिए गए हैं जिसका मालिकाना हक़ बहनों को दिया गया है। मणिपुर में लगभग 2336 बेघरों को रहत पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत 5,477 उद्यमियों के लिए 114 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और 60,000 लोगों को रोजगार दिया गया है।

सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, प्रधानमंत्रीजी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए कृतसंकल्पित है

खेल जगत के लोगों और एक्स-सर्विसमेन से संवाद

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 26 नवंबर 2021 को इम्फाल में खेल जगत के लोगों और एक्स-सर्विसमेन के साथ अलग-अलग संवाद किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा रक्षा और खेल क्षेत्र में किये गए कार्यों की विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी, मणिपुर के भाजपा प्रभारी एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा, सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल एल.एन. सिंह सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता संभालने के पश्चात् देश के रक्षा क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन आया है। भारतीय सेना के तीनों अंगों की ताकत बढ़ी है। कांग्रेस कार्यकाल में भारतीय फ़ौज की ख़राब हालात पर आक्रोशित होते हुए उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान से जब सीमावर्ती क्षेत्रों में गोलीबारी होती थी तो दिल्ली तक संदेश पहुंचने में बहुत समय लगता था और दिल्ली से भी केवल 'वेट और वाच' का संदेश दिया जाता था। अब समय बदला है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पाकिस्तान से सीमा पर गोलीबरी होती है तो तुरंत करारा जवाब दिया जाये, अब दिल्ली से ऑर्डर लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि "हम न किसी से आंख झुकाकर बात करेंगे, ना ही आंख उठाकर बात करेंगे, हम आंख में आंख डालकर बात करेंगे।" सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, प्रधानमंत्रीजी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए कृतसंकल्पित है।

श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के गठन के बाद 'वन रैंक, वन पेंशन' लागू किये जाने की चर्चा करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ओआरओपी के लिए अब तक लगभग 42,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। जवानों की बहुत दिनों से लंबित इस मांग को पूरा किया गया, जबकि निवर्तमान यूपीए सरकार के मंत्री पी चिदंबरम ने वन रैंक वन पेंशन के नाम पर केवल 500 रुपये की टोकन राशि आवंटित की थी जो कि जवानों के साथ बस एक भद्दा मजाक था।

कांग्रेस कार्यकाल में रक्षा सौदे में हुए घोटाला पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान बिना कमीशन के कोई रक्षा सौदा नहीं होता था। इससे हमारे रक्षा बलों को बहुत

'हमारी सरकार ने हर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 25 नवंबर, 2021 को गोवा में सतारी तालुका, वालपो और बिचोलिम विधानसभा के पार्टी कार्यकर्ताओं के आयोजित सम्मेलनों को संबोधित किया और उनसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गोवा की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को घर-घर पहुंचाने की अपील करने के साथ-साथ चुनाव में एकजुट होकर पुनः भारी बहुमत से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोक-कल्याणकारी सरकार बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री एवं सांसद भाऊ श्रीपद नायक, प्रदेश अध्यक्ष श्री सदानंद तनावड़े, गोवा के स्वास्थ्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे, राष्ट्रीय महामंत्री श्री सीटी रवि और राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्य सभा सांसद श्री जफ़र इस्लाम सहित कई मंत्री, विधायक, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इसी सर्वसमावेशी एवं सर्व-स्पर्शी विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल तक कांग्रेस ने जो सरकारें चलाईं, उसमें लोगों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया जाता था और बस चुनाव के समय झूठे वादे कर वोट हड़प लो। हमारी सरकार ने हर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है। देश में कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के 80 करोड़ लोगों को पिछले साल अप्रैल से लेकर नवंबर तक और इस वर्ष अप्रैल से लेकर अगले साल मार्च तक 'गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया है जो हमारी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि दयानंद सोशल सिक्योरिटी योजनाओं के तहत 1.36 लाख गोवावासियों को 2,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया गया है।

श्री नड्डा ने कहा कि एनआईटी, गोवा में गोवावासियों के लिए 40 प्रतिशत सीट आरक्षित हुआ है। 2016 में एक आईआईटी भी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि गोवा में भाजपा सरकार आने के बाद से अपराध पर लगाम लगा है। 2013 के बाद से गोवा में अपराध दर में 101 फीसदी की कमी आई है। क्राइम रेट 101 प्रतिशत नीचे आया है जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक बनाया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 19 से बढ़कर 55 हुई है। ■

नुकसान हुआ था, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने से पहले यूपीए सरकार के 10 साल में कोई रक्षा खरीद ही नहीं हुई थी। ये लोग (पहले की सरकारें) देश को कहां ले गए थे? फौजियों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं था। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने देश के डिफेन्स को संकट में डाल रखा था। भारतीय फ़ौज को इसकी बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में 36 राफेल लड़ाकू विमानों को भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया है। 28 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलिकॉप्टर खरीदे गए हैं। एमआरएसएएम (MRSAM) और आर्टिलरी गन खरीदी गई हैं। 1.86 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट बने हैं। 5 लाख असॉल्ट राइफलें भी लाई गई हैं। ये खरीदारी 22 साल बाद की गई है।

श्री नड्डा ने श्री नरेन्द्र मोदी सरकार में सशक्त सेना की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 6 वर्षों में नागरिक हताहतों की संख्या में लगभग 79 प्रतिशत की कमी आई है। सशस्त्र बलों की हताहतों की संख्या में भी लगभग 23 प्रतिशत की कमी आई है।

श्री नड्डा ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीमा सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए सीमा पर इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया और अब 24 घंटे में हमारी आर्मी हर क्षेत्र में भारतीय सीमा पर पहुंचाने में सक्षम है। भारत-चीन सीमा पर 683 किलोमीटर लंबी 32 नई सीमा सड़कें बनाई जा रही हैं।

खेल जगत के लोगों से संवाद करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि मणिपुर का खेलों से गहरा नाता है और राज्य के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में कई पदक जीते हैं। मणिपुर देश में खेल के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' मूवमेंट की शुरुआत की।

श्री नड्डा ने कहा कि देश में 1,000 एथलीटों का चयन किया गया है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ सालाना 5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने वाले बेहतरीन खिलाड़ी विश्व पटल पर दे सकें। ■

'भाजपा तमिल गौरव, तमिल संस्कृति और दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल के साथ खड़ी है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 24 नवंबर, 2021 को तमिलनाडु के तिरुपुर का दौरा किया। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा, "जब मैं तमिलनाडु आता हूं, तो मुझे लगता है कि जो चुनौती हमारे सामने है वह और अधिक गंभीर हो रही है क्योंकि यहां लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से यहां शुरू किए जा रहे सभी विकास कार्यों को रोका जा रहा है। विकास प्रक्रिया को मोड़ने का काम किया जा रहा है जो किसी परिवार के शासन के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन तमिलनाडु के लोगों के लिए नहीं।"

डीएमके भ्रष्टाचार और वंशवाद से ग्रस्त है और वंशवादी दलों से लड़ने का एकमात्र तरीका भाजपा को विकल्प के रूप में रखना है

द्रमुक सरकार की आलोचना करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि एमके स्टालिन सरकार राज्य के सांस्कृतिक और पवित्र मूल्यों का गला घोंटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने हमेशा व्यवस्था को चुनौती दी है। यहां हमेशा निरुत्साहित और अनादर करने का प्रयास होता रहता है और यह भगवान मुरुगन का अनादर नहीं है; यह तमिलनाडु के सांस्कृतिक लोकाचार का अनादर है। हम इसके रक्षक हैं और हमें इस मानसिकता से लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु के गौरव, तमिल संस्कृति और दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल के साथ खड़े हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि डीएमके भ्रष्टाचार और वंशवाद से ग्रस्त है और वंशवादी दलों से लड़ने का एकमात्र तरीका भाजपा को विकल्प के रूप में रखना है। "डीएमके और भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवार समानार्थी हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप यहां जो वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी चुनौतियां देशव्यापी हैं। वंशवादी पार्टी से लड़ने का एकमात्र तरीका उसके विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लाना है।

श्री नड्डा ने कहा कि विचारधारा की बात करने वाली पार्टियों को पारिवारिक पार्टियों तक सीमित कर दिया गया है। "आप कश्मीर से शुरू करें और दक्षिण तक जाए, तो आप पाएंगे कि 70 वर्षों में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती आयी है। हम पाते हैं कि जो पार्टियां विचारधाराओं के बारे में बात करती थीं, वे पारिवारिक पार्टियों में सिमट गई हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है। जिसका एकमात्र जवाब भाजपा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल भी एक पारिवारिक पार्टी में सिमटकर रह गए हैं।"

टीकाकरण कार्यक्रम की आलोचना का जिक्र करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, "विपक्षी दल कह रहे थे कि यह भाजपा का टीका है और मोदी का टीका है। अब सभी मुख्यमंत्रियों को मोदी का टीका और भाजपा का टीका लग गया है। इन नेताओं ने प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विरोध कर देश का विरोध किया है। इन्होंने देश की जनता के साथ विश्वासघात करने के साथ ही वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम का माहौल पैदा करने का प्रयास किया है।"

श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता को स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन देना चाहती है। उन्होंने कहा, "हम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मूल सिद्धांत के साथ स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन चाहते हैं। हमें सबके लिए मिलकर काम करना होगा और इसके लिए सभी का समर्थन लेना होगा।" ■

सभी 14 शहरी निकायों में भाजपा की शानदार जीत

भाजपा ने त्रिपुरा निकाय चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी 14 शहरी निकायों में जीत हासिल की। इन सभी सीटों पर 25 नवंबर, 2021 को मतदान हुआ था। चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणामों के अनुसार भाजपा ने त्रिपुरा नगरपालिका चुनावों में 334 नगरपालिका सीटों में से 329 पर जीत हासिल की, जो कुल सीटों का 98.50 प्रतिशत है। अगरतला नगर परिषद् में भी भाजपा को सभी 51 सीटों पर जीत मिली और इसके साथ ही पहली बार अगरतला नगर निगम बिना विपक्ष के काम करेगा। इन चुनावों में भाजपा ने 112 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की और शेष 222 सीटों पर हुए मतदान में 81.54 प्रतिशत वोट डाले गए।

14 शहरी निकायों की शेष 222 सीटों में से 217 सीटों पर भाजपा विजयी हुई, जबकि पिछले नगर निकाय चुनावों में सभी शहरी निकायों में जीत हासिल करने वाली माकपा केवल तीन सीटें जीतने में कामयाब हुई। तृणमूल कांग्रेस और टीआईपीआरए मोथा ने केवल एक-एक सीटें जीतीं। राज्य में 20 में से 14 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ था।

पार्टी	भाजपा	सीपीएम	टीएमसी	कांग्रेस	टीआईपीआरए	कुल
वार्ड	329	3	1	0	1	334

यह आशीर्वाद हमें कल्याण कार्य करने की ताकत देते हैं: नरेन्द्र मोदी

त्रिपुरा निकाय चुनावों में भाजपा की जीत को सुशासन के पक्ष में मतदाताओं का संदेश बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया, "त्रिपुरा के लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वे सुशासन की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। मैं उन्हें भाजपा को स्पष्ट समर्थन देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। ये आशीर्वाद हमें त्रिपुरा में प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करने की और अधिक शक्ति प्रदान करेगा।

मैं त्रिपुरा के भाजपा कार्यकर्ताओं की सराहना करना चाहता हूं जिन्होंने जमीन पर अथक परिश्रम किया और लोगों की सेवा की। श्री बिप्लब देब के नेतृत्व में राज्य सरकार कई पहल करने में सबसे आगे रही है, जिसे लोगों ने उन्हें विधिवत आशीर्वाद दिया है।

यह लोकतंत्र की जीत है: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने निकाय चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं को उनकी शानदार जीत पर बधाई देते हुए कहा, "मैं इस ऐतिहासिक जीत के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब, राज्य भाजपा अध्यक्ष और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। यह लोकतंत्र की जीत है।"

ऐतिहासिक जीत: बिप्लब कुमार देब

मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देब ने कहा, "त्रिपुरा शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की यह ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विकास नीतियों में त्रिपुरा के लोगों के विश्वास को दर्शाता है। यह प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के आदर्श वाक्य में जनता के भरोसे को भी दर्शाता है।"

त्रिपुरा के लोगों ने वोट डालकर सभी को करारा जवाब दिया है, जिससे 98.50 प्रतिशत सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित हुई है।

श्री देब ने कहा कि जिन लोगों ने त्रिपुरा को बदनाम कर फूट डालने का प्रयास किया, उन्हें देखना चाहिए कि कैसे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के लिए मतदान किया है। चुनावी जनादेश भी उन लोगों के लिए एक जवाब था, जिन्होंने त्रिपुरा का अपमान करने और साजिशों से इसे नीचा दिखाने का प्रयास किया। ■

नवंबर, 2021 में दूसरा सबसे अधिक जीएसटी संग्रह, 1.31 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा

नवम्बर, 2021 महीने में जीएसटी राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व की तुलना में 25 प्रतिशत और 2019-20 की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा एक दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार नवम्बर, 2021 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,31,526 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीजीएसटी 23,978 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 31,127 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 66,815 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रह किए गए 32,165 करोड़ रुपये सहित) और उपकर (सेस) 9,606 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रह किए गए 653 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी के लिए 27,273 करोड़ रुपये और आईजीएसटी से एसजीएसटी के लिए 22,655 करोड़ रुपये का निपटान किया। नवम्बर, 2021 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 51,251 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 53,782 करोड़ रुपये है। केन्द्र ने 3 नवम्बर, 2021 को जीएसटी मुआवजे के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को 17,000 करोड़ रुपये भी जारी किए।

लगातार दूसरे महीने जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। नवम्बर, 2021 माह के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 25 प्रतिशत और 2019-20 की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक रहा। इस महीने के दौरान वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व 43 प्रतिशत अधिक और घरेलू लेन-देन (सेवाओं के आयात सहित) से प्राप्त राजस्व पिछले साल के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक रहा।

नवम्बर, 2021 के लिए जीएसटी राजस्व जीएसटी की शुरुआत के बाद से दूसरा सबसे अधिक राजस्व रहा। यह अप्रैल, 2021 के बाद दूसरा बड़ा संग्रह है, जो साल के अंत के राजस्व से संबंधित था और पिछले महीने के संग्रह से अधिक रहा, इसमें त्रैमासिक दाखिल की जाने वाली आवश्यक रिटर्न का प्रभाव भी शामिल रहा है। यह काफी सीमा तक आर्थिक सुधार की प्रवृत्ति के अनुरूप है।

अधिक जीएसटी राजस्व का यह वर्तमान रुझान विभिन्न नीतिगत और प्रशासनिक उपायों का परिणाम रहा है, जो अतीत में अनुपालन में सुधार करने के लिए उठाए गए हैं। केन्द्रीय कर प्रवर्तन एजेंसियों ने राज्य के समकक्षों के साथ जीएसटीएन द्वारा विकसित विभिन्न आईटी उपकरणों की मदद से बड़े कर चोरी के मामलों का पता लगाया है, जिनमें मुख्य रूप से नकली चालान से संबंधित मामले शामिल हैं, जो संदिग्ध करदाताओं का पता लगाने के लिए रिटर्न, चालान और ई-वे बिल डेटा का उपयोग करते हैं।

पिछले वर्ष बड़ी संख्या में पहल शुरू की गई हैं जिनमें सिस्टम क्षमता में बढ़ोतरी, रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद रिटर्न फाइल न करने वालों पर कार्रवाई, रिटर्न की ऑटो-पॉपुलेशन, ई-वे बिलों को अवरुद्ध करना और रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करना आदि शामिल हैं। इससे पिछले कुछ महीनों के दौरान रिटर्न दाखिल करने में लगातार सुधार हुआ है। ■

भारत ने संस्थापित बिजली क्षमता में 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोत का लक्ष्य प्राप्त किया

गैर-जीवाश्म ऊर्जा आधारित कुल संस्थापित क्षमता 156.83 गीगावॉट

सीओपी-21 में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के हिस्से के रूप में भारत ने 2030 तक अपनी संस्थापित बिजली क्षमता का 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई थी। देश ने नवंबर, 2021 में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दो दिसंबर को जारी एक बयान के अनुसार देश की संस्थापित अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता आज 150.05 गीगावॉट है, जबकि इसकी परमाणु ऊर्जा आधारित संस्थापित बिजली क्षमता 6.78 गीगावॉट है। इससे कुल गैर-जीवाश्म आधारित संस्थापित ऊर्जा क्षमता 156.83 गीगावॉट हो जाती है, यह 390.8 गीगावॉट की कुल संस्थापित बिजली क्षमता का 40.1% है जो कि हाल ही में संपन्न सीओपी-26 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के अनुरूप है। सरकार वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावॉट की संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ■

2021-22 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के जीडीपी में 8.4 प्रतिशत की हुई वृद्धि

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 30 नवंबर को जारी एक प्रेस नोट के अनुसार 2021-22 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में लगातार स्थिर मूल्यों (2011-12) पर जीडीपी 35.73 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 32.97 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले दूसरी तिमाही में 7.4 प्रतिशत कमी की तुलना में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में मूल कीमतों पर तिमाही जीवीए 2021-22 में 32.89 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 30.32 लाख करोड़ रुपये रहा था, इससे 8.5 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

2021-22 की दूसरी तिमाही में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर अनुमानित जीडीपी 55.54 लाख करोड़ होने का अनुमान है जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में यह 47.26 लाख करोड़ रुपये था, जिससे 17.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रदर्शित होती है जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 4.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए बुनियादी मूल्य पर स्थिर (2011-12) मूल्यों पर तिमाही जीवीए अनुमानित रूप से 49.70 लाख करोड़ रुपये है जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 42.54 लाख करोड़ रुपये रहा था, इससे 16.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रदर्शित होती है।

अप्रैल-सितंबर 2021-22 (एच1 2021-22) में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 59.92 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 68.11 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो एच1 2021-22 में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 15.9 प्रतिशत के संकुचन के मुकाबले 13.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। एच-1 2021-22 में मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 86.15 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 106.77 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो एच1 2021-22 में 23.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 13.4 प्रतिशत के संकुचन को दर्शाता है।

रत्न एवं आभूषण का निर्यात वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में दोगुने से भी अधिक हुआ

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 27 नवंबर को कहा कि भारत विश्व में सबसे बड़े हीरा व्यापारिक हब के रूप में उभर सकता है। उन्होंने कहा कि हमने खुद को हीरे की कटिंग तथा पॉलिशिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ी हस्ती के रूप में स्थापित कर लिया है।

उल्लेखनीय है कि रत्न एवं आभूषण का निर्यात इस वित्त वर्ष के पहले सात महीनों— अक्टूबर, 2021 तक 23.62 बिलियन डॉलर तक रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 11.69 बिलियन डॉलर (+ 102.9 प्रतिशत) की तुलना में दोगुने से भी अधिक रहा। श्री गोयल ने कहा कि हमारे विनिर्माताओं की उत्कृष्ट गुणवत्ता ने हमें दुबई-यूएई, अमेरिका, रूस, सिंगापुर, हांगकांग तथा लातिनी अमेरिका जैसे बाजारों में प्रवेश करने में सक्षम बनाया है। ■

भारत सरकार को अक्टूबर, 2021 तक कुल 12,79,699 करोड़ रुपये प्राप्त हुए

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार को अक्टूबर, 2021 तक कुल 12,79,699 करोड़ रुपये (कुल प्राप्तियों के संबंधित बजट अनुमान 2021-22 का 64.8 प्रतिशत) प्राप्त हुए, जिनमें 10,53,135 करोड़ रुपये का कर राजस्व (केंद्र के लिए विशुद्ध राशि); 2,06,842 करोड़ रुपये का गैर कर राजस्व और 19,722 करोड़ रुपये की गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 10,358 करोड़ रुपये के ऋणों की वसूली और 9,364 करोड़ रुपये की मिलीजुली पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। अक्टूबर, 2021 तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 3,07,687 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा 18,26,725 करोड़ रुपये (संबंधित बजट अनुमान 2021-22 का 52.4 प्रतिशत) का कुल खर्च किया गया है, जिनमें से 15,73,455 करोड़ रुपये राजस्व खाते में हैं और 2,53,270 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते में हैं। कुल राजस्व व्यय में से 3,99,737 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 2,09,916 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं। ■

ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने कराया पंजीकरण

करीब 48 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिक पुरुष हैं और शेष 52 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं हैं। लगभग 61 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिक 18-40 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जबकि लगभग 22 प्रतिशत 40-50 वर्ष आयु वर्ग के हैं

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी लाते हुए ई-श्रम पोर्टल (असंगठित श्रमिकों) का राष्ट्रीय डेटाबेस) ने एक दिसंबर को 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। यह 26 अगस्त, 2021 को शुरू हुआ था।

इस उपलब्धि को 'संकल्प से सिद्धि' की यात्रा बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देश के करोड़ों श्रमिकों और कामगारों का सामर्थ्य आज नए भारत का आधारस्तंभ बन रहा है। उनकी सामाजिक सुरक्षा में ही देश का मजबूत भविष्य छिपा है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, सड़क विक्रेताओं, घरेलू श्रमिकों, कृषि श्रमिकों सहित अन्य असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ईएसएचआरएएम (ई-श्रम) पोर्टल (www.eshram.gov.in) 26 अगस्त, 2021 को शुरू किया गया था।

आधार से जुड़े ई-श्रम पोर्टल का उपयोग असंगठित श्रमिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए किया जाएगा। ई-श्रम पोर्टल पर सभी पात्र पंजीकृत श्रमिकों को पॉलिसी जारी होने की तारीख से पीएमएसबीवाई के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है।

भारत सरकार ने असंगठित कामगारों के पास जाकर पंजीकरण की सुविधा प्रदान की है। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) देशभर में अपने 4 लाख से ज्यादा केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। पंजीकरण सुविधा का विस्तार करने के लिए राज्य सरकारें भी 17,337 से ज्यादा राज्य सेवा केंद्रों को ई-श्रम पोर्टल के साथ जोड़ चुकी हैं। कामगार खुद ई-श्रम पोर्टल पर जाकर भी पंजीकरण कर सकते हैं। फिलहाल, 81% पंजीकरण सीएससी और एसएसके द्वारा किया जा रहा है और शेष 19% स्वयं पंजीकरण किया जा रहा है।

करीब 48 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिक पुरुष हैं और शेष 52 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं हैं। ट्रांसजेडरों को भी ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। ई-श्रम पर अब तक 2,380 ट्रांसजेंडर पंजीकृत किए जा चुके हैं। लगभग 61 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिक 18-40 वर्ष आयु वर्ग के हैं जबकि लगभग 22 प्रतिशत 40-50 वर्ष आयु वर्ग के हैं।

ई-श्रम पोर्टल के तहत श्रमिकों को उनके व्यवसाय से पहचान दिलाने के लिए व्यवसाय भी दर्ज किया जा रहा है। यह सरकारों को असंगठित कामगारों के सभी वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा वाली कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने में सुविधा प्रदान करेगा। 30 व्यापक क्षेत्र की श्रेणियों वाली गतिविधियां, 190 बड़े व्यवसायों के क्षेत्र और करीब 400 व्यवसाय हैं। यह व्यवसायों का राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण, 2015 पर आधारित है। ■

देश की 50 प्रतिशत टीका-योग्य आबादी का पूर्ण टीकाकरण हुआ

देश की 50 प्रतिशत टीका-योग्य आबादी पूरी तरह से टीकाकृत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा कि बधाई हो भारत। यह बहुत गर्व का क्षण है, क्योंकि 50 प्रतिशत से अधिक योग्य आबादी को अब पूरी तरह से टीकाकृत किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लेने पर हर्ष व्यक्त किया। श्री मंडाविया के ट्वीट के उत्तर में प्रधानमंत्री ने छह दिसंबर को कहा कि भारत के टीकाकरण अभियान ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाने के लिये इस निरंतरता को बनाये रखना जरूरी है। साथ ही, श्री मोदी ने यह भी कहा कि मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का ध्यान रखने सहित कोविड-19 से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का बराबर पालन किया जाता रहे। ■

भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 127.93 करोड़ के पार

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार छह दिसंबर की सुबह सात बजे तक (अनन्तिम रिपोर्ट) देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 127.93 करोड़ (1,27,93,09,669) के पार पहुंच गया। इसे 1,30,65,773 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।

भारत की रिकवरी दर इस समय 98.35 प्रतिशत है। सक्रिय मामले इस समय देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.28 प्रतिशत है, जो मार्च, 2020 से अपने न्यूनतम स्तर पर है। समग्र रूप से भारत में अब तक 64.82 करोड़ से अधिक (64,82,59,067) जांचें की गईं हैं। ■

भारतीय राष्ट्र का मूल स्वरूप

अटल बिहारी वाजपेयी

राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र की स्पष्ट कल्पना लेकर चलें। राष्ट्र कुछ संप्रदायों अथवा जनसमूहों का समुच्चय मात्र नहीं, अपितु एक जीवमान इकाई है, जिसे जोड़-तोड़कर नहीं बनाया जा सकता। इसका अपना व्यक्तित्व होता है, जो उसकी प्रकृति के आधार पर कालक्रम का परिणाम है। उसके घटकों में राष्ट्रीयता की यह अनुभूति, मातृभूमि के प्रति भक्ति, उसके जन के प्रति आत्मीयता और उसकी संस्कृति के प्रति गौरव के भाव में प्रकट होती है। इसी आधार पर अपने-पराये का, शत्रु-मित्र, अच्छे-बुरे और योग्य-अयोग्य का निर्णय होता है। जीवन की इन निष्ठाओं तथा मूल्यों के चारों ओर विकसित इतिहास, राष्ट्रीयत्व की भावना घनीभूत करता हुआ, उसे बल प्रदान करता है। उसी से व्यक्ति को त्याग और समर्पण की, पराक्रम और पुरुषार्थ की, सेवा और बलिदान की प्रेरणा मिलती है।

भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। स्वतंत्रता की प्राप्ति से, इसके चिरकालीन इतिहास में एक नये अध्याय का प्रारंभ हुआ। किसी नवीन राष्ट्र का जन्म नहीं। भारतीय राष्ट्र का मूल स्वरूप राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक एकता की अनुभूति ही राजनीतिक एकता के पक्ष की प्रेरक शक्ति रही है। राजनीतिक एकता के अभाव ने देश की सांस्कृतिक धारा को कभी खण्डित नहीं होने दिया। जहां एक ओर हम भारत की संस्कृति से अभिन्न रूप से संबद्ध अनेक राजनीतिक इकाइयों के प्रति उदासीन तथा सहिष्णु रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति से भिन्न उसके विकृत अथवा विरोधी भाव पर आधारित, कोई भी राजनीतिक सत्ता हमें मान्य नहीं हुई। हम सदैव उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं।

> **भारतीय राष्ट्र का मूल स्वरूप राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक एकता की अनुभूति ही राजनीतिक एकता के पक्ष की प्रेरक शक्ति रही है**

विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। हमने एकरूपता की नहीं, अपितु एकता की कामना की है। फलतः देश में अनेक उपासना पद्धतियों, पंथों, दर्शनों, जीवन-प्रणालियों, भाषाओं, साहित्यों और कलाओं का विकास हुआ, जो सम्पन्नता की द्योतक हैं। हमें उनके प्रति अपनत्व और गौरव का भाव लेकर चलना होगा। किन्तु, विविधता के नाम पर विभाजन को प्रोत्साहन देना भूल होगी। भारतीय संस्कृति कभी किसी एक उपासना पद्धति से बंधी नहीं रही और न उसका आधार प्रादेशिक ही रहा है। मजहब अथवा क्षेत्र के आधार पर पृथक् संस्कृति की चर्चा तर्क-विरुद्ध ही नहीं, भयावह भी है, क्योंकि वह राष्ट्रीय एकता की जड़ पर ही कुठाराघात करती है।

क्षेत्र, प्रदेश, जाति, पंथ, भाषा, भूषा आदि के आधार पर भारतीय जन की पृथकता की कल्पना भ्रामक है। उनके आधार पर भारत में अनेक राष्ट्रों अथवा राष्ट्रीयताओं के अस्तित्व का विचार भी मूलतः अशुद्ध है। हम एक राज्य में रहने के कारण एक नहीं हैं, अपितु हम एक हैं, इसलिए भारत एक राष्ट्र है। ■

हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोगों का असामयिक निधन

भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्यकर्मियों का तमिलनाडु के कुन्नूर में आठ दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में असामयिक निधन हो गया। जनरल रावत ने भारतीय सेना के उच्च रक्षा संगठन में दूरगामी सुधारों की शुरुआत की। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के संयुक्त थिएटर कमांड की नींव रखने और सैन्य उपकरणों के बढ़ते स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इससे पहले जनरल रावत 17 दिसंबर, 2016 से 31 दिसंबर, 2019 तक सेना प्रमुख की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उन्हें 31 दिसंबर, 2019 को भारत का पहला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनरल रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मैं अत्यंत दुःखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया। उन्होंने अत्यंत कर्मठता से भारत की सेवा की। मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।

उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे। एक सच्चे देशभक्त के रूप में उन्होंने सशस्त्र बलों और समस्त सुरक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण में बहुमूल्य योगदान दिया। सामरिक मामलों में उनकी दूरदृष्टि असाधारण थी। उनके निधन से मुझे गहरा सदमा पहुंचा है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत के प्रथम 'सीडीएस' के रूप में जनरल बिपिन रावत ने रक्षा सुधारों सहित सशस्त्र बलों से संबंधित

विभिन्न आयामों पर उत्कृष्ट काम किया। उन्हें सेना में अपनी सेवाएं देने का व्यापक अनुभव था। भारत कभी भी उनकी असाधारण सेवा को नहीं भूलेगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए दुःखद हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल श्री विपिन रावत, उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत सहित सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों एवं चालक दल के सदस्यों के असामयिक निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया।

श्री नड्डा ने अपने शोक संदेश में कहा कि मैं इस दुःखद, हृदयविदारक और झकझोर कर रख देने वाले हादसे के समाचार से अत्यंत शोकाकुल, स्तब्ध और व्यथित हूं। यह समग्र राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई असंभव है। पूरा राष्ट्र अपने नायकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।

दिवंगत सैन्यकर्मियों के सम्मान में संसद के दोनों सदनों में नौ दिसंबर को कुछ पलों का मौन रखा गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नौ दिसंबर को संसद में दिवंगत सैन्यकर्मियों को अपनी और पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की।

रक्षा मंत्री ने पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा में दिये गए अपने बयान में कहा कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत आठ दिसंबर को वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के छात्रों से संवाद करने के लिए पूर्व निर्धारित यात्रा पर थे।

श्री सिंह के अनुसार, इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 की मृत्यु हो गयी जिनमें सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी शामिल हैं।

श्री सिंह ने बताया कि अन्य मृतकों में सीडीएस के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, सीडीएस के सैन्य सलाहकार एवं स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर प्रतीक सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट अधिकारी राणा प्रताप दास, जूनियर अधिकारी अरक्कल प्रदीप, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेन्द्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक वीर साई तेजा शामिल थे।

उन्होंने बताया कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र के लिए एक बहुत ही दुःखद दिन है हमने अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत ही दुःखद दुर्घटना में खो दिया है। जनरल बिपिन रावत सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ मातृभूमि की सेवा की है। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मैं बहुत ही दुःखी हूं। ■

21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों पर भाजपा अध्यक्ष का संबोधन

'महामारी, जलवायु परिवर्तन और कट्टरवाद की चुनौतियों को लेकर हमारा प्रतिसाद 21वीं सदी में पथ प्रदर्शक का काम करेगा'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 01 दिसंबर, 2021 को यूनाइटेड रशिया पार्टी द्वारा आयोजित '21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियां: इंटरपार्टी डायमेंशन' संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस संगोष्ठी का आयोजन यूनाइटेड रशिया पार्टी की 20वीं वर्षगांठ के अवसर किया गया है। इस संगोष्ठी का उद्‌घाटन यूनाइटेड रशिया पार्टी के अध्यक्ष श्री डीए मेदवेदेव ने किया। संगोष्ठी में दुनिया भर के राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मंच पर बोलने के अवसर के लिए यूनाइटेड रशिया पार्टी के सुप्रीम काउंसिल के अध्यक्ष श्री बोरिस ग्रिज़लोव को धन्यवाद दिया।

संबोधन के प्रमुख बिंदु:

- भारत और रूस लंबे समय से एक मजबूत साझेदारी को निभाते आये हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत और रूस के बीच दोस्ती और साझेदारी सबसे स्थिर रही है। भारतीय रूस की प्रशंसा करते हैं और रूस को भारत का खास दोस्त माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी और यूनाइटेड रशिया पार्टी के बीच पार्टी-टू-पार्टी संवाद दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मददगार साबित होगा।
- भाजपा लगभग 20 करोड़ प्राथमिक सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और यूनाइटेड रशिया पार्टी दोनों देशों के बीच की कड़ी को मजबूती देती है। दोनों राजनीतिक दल इस दोस्ती और आपसी सम्मान से प्रेरणा लेते हैं जो राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संबंधों से भी स्पष्ट है।
- तीन प्रमुख चुनौतियों के प्रति हमारा प्रतिसाद— 'महामारी, जलवायु परिवर्तन और कट्टरवाद की चुनौतियों को लेकर हमारी प्रतिक्रिया 21वीं सदी में पथ प्रदर्शक का काम करेगा।' तीनों क्षेत्रों में भारत और रूस साझा और वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक साथ जो हासिल कर सकते हैं, वह हमारे साझा क्षेत्र के साथ-साथ विश्व व्यवस्था में शांति और समृद्धि का निर्धारण करेगा।
- रूस ने हमें जो मदद दी है, उसकी भारत में बहुत सराहना होती है। रूस ने इस साल की शुरुआत में महामारी की दूसरी लहर के दौरान विशेष रूप से ऑक्सीजन और अन्य आपातकालीन सामग्री भारत को प्रदान की।
- आज भारत में कोविड की स्थिति काफी बेहतर है। हमने अपने नागरिकों को टीकों की 124 करोड़ से अधिक खुराक दी है और हमने अपनी लगभग पूरी योग्य आबादी को कम से कम एक खुराक देने का काम किया है।
- सबसे बड़े और सामाजिक रूप से जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में भाजपा ने कोविड महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर राहत अभियान चलाया। भाजपा ने एक विशेष राहत अभियान 'सेवा ही संगठन' चलाया। संकट की विकरालता के कारण सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने घरों से बाहर निकल कर बीमार और जरूरतमंद लोगों की सेवा की, जिसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता भी नहीं की।
- हम विनिर्माण क्षेत्र में विशेष रूप से रक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रूसी निवेश और साझेदारी चाहते हैं, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
- भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में अत्यधिक प्रतिबद्ध है। भारत और रूस को ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों के विकास में एक दूसरे का सहयोग करने की आवश्यकता है।
- अफगानिस्तान की स्थिरता और यह आशा कि यह एक बार फिर आतंकवाद और नशीले पदार्थों का अभयारण्य नहीं बनेगा, इस प्रतिबद्धता को भारत और रूस दोनों ने एक बार फिर साझा किया जाता है। यह दोनों देशों के लिए आपसी चिंता का विषय है। इस क्षेत्र के ऐतिहासिक हितधारक और अफगानिस्तान के मित्र के रूप में भारत और रूस को क्षेत्र में स्थिरता और शांति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
- भाजपा और यूनाइटेड रशिया पार्टी के बीच पार्टी-टू-पार्टी आदान-प्रदान इस वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में और भी अधिक योगदान देगा। ■

गहलोत सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है– 'लो और ऑर्डर दो': अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 5 दिसंबर, 2021 को जयपुर (राजस्थान) में जन-प्रतिनिधि महासम्मेलन को संबोधित किया। इस महासम्मेलन में पूरे प्रदेश से आये हुए जन-प्रतिनिधि और सहकारी नेता उपस्थित थे। इससे पहले श्री शाह ने राजस्थान प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक के समापन सत्र को भी संबोधित किया और पार्टी पदाधिकारियों को आगे बढ़ने के मंत्र दिए। जन-प्रतिनिधि महासम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सतीश पुनिया, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, वरिष्ठ भाजपा

नेता श्री ओम प्रकाश माथुर, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह, श्रीमती अलका सिंह, श्रीमती जसकौर मीणा, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्री गुलाब चंद कटारिया सहित कई वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी, नेता, विधायक एवं सांसद आदि उपस्थित थे। इससे पहले जयपुर पहुंचने पर श्री शाह का भव्य स्वागत हुआ। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल सीतापुरा स्थित जेईसीसी कन्वेशन हॉल तक की लगभग 9 किलो मीटर की दूरी एक रोड शो में तब्दील हो गई। इस दौरान दर्जनों स्थानों पर श्री शाह का राजस्थानी लोकनृत्य, लोकगीतों एवं पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया।

विशाल जन-समुदाय को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन और विचारधारा के आधार पर चलती है और सनातन संस्कृति को लेकर आगे बढ़ती है।

राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए श्री शाह ने कहा कि पूरे राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की व्याख्या ही बदल गई है। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है– 'कानून और व्यवस्था' लेकिन गहलोत सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। गहलोत सरकार में राजस्थान में लूट के मामलों में 40 प्रतिशत, अपहरण के मामलों में 25 प्रतिशत, बलात्कार के मामलों में 21 प्रतिशत और बच्चियों के खिलाफ बलात्कार के मामलों में लगभग 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाय, कम है। राजस्थान में कई पुजारियों की हत्या हुई, मंदिरों में चोरियां हुईं। कांग्रेस की गहलोत सरकार के राज में तो मंदिर भी सुरक्षित नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राजस्थान में 40 हजार से अधिक गांवों को खुले में शौच के दंश से मुक्त किया, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 14 लाख घर बनाने का कार्य किया, लगभग 1200

किलोमीटर से अधिक की रेल परियोजनाओं का पूरा किया, लगभग 50 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई और भारतमाला परियोजना के तहत प्रदेश में लगभग 2400 किलोमीटर सड़कें बनाईं।

श्री शाह ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि राजस्थान में विकास की नई कहानी लिखनी है, विकास को नई गति देनी है और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की अवधारणा पर सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास की गाथा लिखनी है तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाना जरूरी है। ■

जो दल स्वयं लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हों, वे लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं: नरेन्द्र मोदी

हमारा संविधान सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है, हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की महान परंपरा, अखंड धारा उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है

गत 26 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी संसद में 'संविधान दिवस समारोह' में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संबोधित किया। माननीय राष्ट्रपति ने अपने भाषण के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा जिसका लाइव प्रसारण किया गया। माननीय राष्ट्रपति ने संविधान सभा वाद-विवाद का डिजिटल संस्करण, भारत के संविधान की सुलेखित प्रति का डिजिटल संस्करण और भारत के संविधान के अद्यतन संस्करण का विमोचन किया जिसमें अब तक के सभी संशोधन शामिल हैं। उन्होंने 'संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन क्विज' का भी उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिवस बाबासाहेब अम्बेडकर, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, बापू जैसे दुरंदेशी महानुभावों और उन सभी लोगों का नमन करने का है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बलिदान दिए। आज का दिवस इस सदन को नमन करने का है। उन्होंने कहा कि ऐसे दिग्गजों के नेतृत्व में बहुत मंथन और चर्चा के बाद हमारे संविधान का अमृत उभरा। श्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि आज लोकतंत्र के इस सदन को भी नमन करने का दिन है। प्रधानमंत्री ने 26/11 के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी।

> **योग्यता के आधार पर एक परिवार से एक से अधिक लोग जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। समस्या तब आती है जब एक पार्टी पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक ही परिवार द्वारा चलायी जाती है**

उन्होंने कहा कि आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दु:खद दिवस है, जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर मुंबई में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। देश के वीर जवानों ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज उन बलिदानियों को भी नमन करता हूं।

श्री मोदी ने कहा कि हमारा संविधान सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है, हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की महान परंपरा, अखंड धारा उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि इस संविधान दिवस को इसलिए भी मनाना चाहिए, क्योंकि यह हमें इस बात का मूल्यांकन करने का अवसर देता है कि हमारा जो रास्ता है, वह सही है या नहीं है।

प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस मनाने के पीछे छिपी भावना के बारे में बताते हुए कहा कि बाबासाहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी, हम सबको लगा इससे बड़ा पवित्र अवसर क्या हो सकता है कि बाबासाहेब अम्बेडकर ने जो इस देश को जो नजराना दिया है, उसको हम हमेशा एक स्मृति ग्रंथ के रूप में याद करते रहें। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परंपरा की स्थापना के साथ-साथ उसी समय 26 नवंबर को भी 'संविधान दिवस' के रूप में स्थापित कर दिया जाता।

श्री मोदी ने कहा कि परिवार आधारित पार्टियों के रूप में भारत एक तरह के संकट की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहा है, जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है और वह है पारिवारिक पार्टियां।

श्री मोदी ने कहा कि योग्यता के आधार पर एक परिवार से एक से अधिक लोग जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। समस्या तब आती है जब एक पार्टी पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक ही परिवार द्वारा चलायी जाती है। उन्होंने कहा कि संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है, संविधान की एक-एक धारा को भी चोट पहुंची है, जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। श्री मोदी ने सवाल किया कि जो दल स्वयं लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हों, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं?

प्रधानमंत्री ने दोषी भ्रष्ट लोगों को भूलने और उनका महिमामंडन करने की प्रवृत्ति को लेकर भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि हमें सुधार का अवसर देते हुए ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन में महिमामंडित करने से बचना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में अधिकारों को लिए लड़ते हुए भी कर्तव्यों के लिए तैयार करने की कोशिश की थी। उन्होंने आखिर में कहा कि अच्छा होता अगर देश के आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता। आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे लिए आवश्यक है कि कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ें, ताकि अधिकारों की रक्षा हो। ■

केन्द्रीय गृह मंत्री का सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) का दौरा

आज उत्तर प्रदेश में क़ानून का राज है: अमित शाह

गत दो दिसंबर को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्री संजीव बालियान और श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यहां इस विश्वविद्यालय के भूमि-पूजन के साथ ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए जो बहुत बड़ा यज्ञ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें आज एक आहुति और पड़ गई है। इसके साथ ही आस-पास के तीन जनपदों के युवाओं के लिए न केवल पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था होगी, बल्कि अपने घर के पास ही उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाएगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले गन्ना मिलों को बंद करके अपने ही लोगों को बेचने का बड़ा षड्यंत्र चलता था, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी गन्ना मिल न तो बेची गई है और न ही बंद हुई है। अब तक उत्तर प्रदेश के 90 प्रतिशत किसानों के गन्ने का भुगतान हो चुका है। 1.44 लाख करोड़ रुपये का भुगतान पिछले पांच साल में हुआ है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार के पांच साल के मुक़ाबले योगी सरकार के पांच साल में डकैती के मामलों में 70 प्रतिशत की कमी हुई है, हथियार बंद लूट के मामलों में 69 प्रतिशत की कमी आई है, हत्याओं में 30 प्रतिशत, उपद्रव में 33 प्रतिशत और दहेज के कारण मृत्यु के मामलों में साढ़े 22 प्रतिशत की कमी आई है। पिछली सरकार के शासन में यूपी में माफ़ियाराज था और आज उत्तर प्रदेश में क़ानून का राज है। एक ज़माना था कि यहां दंगे होते थे, युवा मारे जाते थे और कई दिनों तक कर्फ्यू रहता था और इन मामलों में एकतरफ़ा केस दर्ज करने की प्रवृत्ति होती थी।

श्री शाह ने कहा कि यहां की जनता ने दो बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। देश के ऐसे बहुत सारे मसले जिन्हें 70 साल से छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था, नरेन्द्र मोदी जी ने सात साल में उन्हें पूरा कर दिया। पूरे देश में कोई नहीं मानता था कि धारा 370 कभी समाप्त होगी, लेकिन नरेन्द्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को संविधान से धारा 370 को खत्म करने का काम किया।

उन्होंने कहा कि कोई नहीं मानता था कि रामजन्म भूमि का फैसला आएगा और राम मंदिर की शुरुआत होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज अयोध्या में आसमान छूते हुए राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। ■

'अंत्योदय को साकार करता उत्तर प्रदेश' पुस्तक का लोकार्पण

पिछले दिनों लेखक डॉ. सौरभ मालवीय की पुस्तक 'अंत्योदय को साकार करता उत्तर प्रदेश' का लोकार्पण केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री श्री महेंद्र पांडेय, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य एवं श्री दिनेश शर्मा, भाजपा उत्तर प्रदेश प्रभारी श्री राधामोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्रदेव सिंह एवं प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री सुनील बंसल उपस्थित थे।

मूलतः माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल में सहायक प्राध्यापक डॉ. सौरभ मालवीय संप्रति बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय में विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूर्व में वे भाजपा राष्ट्रीय मीडिया विभाग से संबद्ध रह चुके हैं।

लेखक ने पुस्तक 'अंत्योदय को साकार करता उत्तर प्रदेश' के माध्यम से भाजपा सरकार की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं पर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक का उद्देश्य है— लोगों को सरकार की जनहितैषी योजनाओं से अवगत कराना, ताकि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सके। इस पुस्तक का प्रकाशन यश पब्लिकेशंस ने किया है। ■

प्रधानमंत्री मोदीजी अनुसूचित जनजाति समाज के उत्थान को लेकर अंतर्मन से काम कर रहे हैं : समीर उरांव

भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जनजाति (एसटी) मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं झारखंड से राज्यसभा सांसद श्री समीर उरांव का कहना है कि मोर्चा जनजाति समाज में पार्टी की विचारधारा का प्रसार कर रहा है; इसके साथ ही इस समाज की प्रमुख समस्याओं— पलायन और बेरोजगारी को दूर करने के लिए संसदीय संकुल विकास योजना बनाने को लेकर कार्य कर रहा है।

पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में श्री समीर उरांव से 'कमल संदेश' के सह संपादक संजीव कुमार सिन्हा एवं कमल संदेश डिजिटल टीम सदस्य विपुल शर्मा ने मोदी सरकार द्वारा जनजाति समुदाय के हितार्थ किए जा रहे कार्यों, भाजपा एसटी मोर्चा की गतिविधियों एवं आगामी योजनाओं पर बातचीत की। प्रस्तुत हैं मुख्यांश—

जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। गत 15 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पहला जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इससे देश भर में क्या संदेश गया?

पिछले 10 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने कैबिनेट में विभिन्न विषयों के साथ अनुसूचित जनजातियों के सम्मान के लिए जनजाति वीर महापुरुष, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में महती भूमिका निभाई थी, ऐसे 'धरती आबा' भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को इसलिए चुना गया कि वे देश की आजादी की लड़ाई के साथ-साथ समाज 'आत्मनिर्भर' हो, इसकी भी चिंता करते थे। वे गांव-गांव में जाकर जन-जागरण करते थे। जहां कहीं भी किसी प्रकार की समस्या, विपत्ति या बीमारी की बात हो, लोग बिरसा मुंडाजी को याद करते थे, उनके पास जाते थे। उनके आत्मीय भाव से लोग संकट से मुक्त हो जाते थे और इस तरह बिरसा मुंडाजी भगवान के रूप में सुविख्यात हो गए।

भगवान बिरसा मुंडाजी राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ आगे बढ़े। इससे अंग्रेजों को काफी परेशानी होने लगी और वे इनको ढूढ़ने लगे। भगवान बिरसा मुंडा ने डोंबारी बुरू से उलगुलान शुरू कर दिया कि अब अंग्रेज को यहां से भगा देना है। डोंबारी बुरू को लेकर इतिहास के पन्नों में ठीक से बातें अंकित नहीं है। जालियावाला बाग कांड से पूर्व 1896 के आसपास डोंबारी बुरू में उलगुलान के बाद जब इन लोगों की बैठक हो रही थी, उस समय अंग्रेज सिपाहियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इसमें भगवान बिरसा मुंडाजी के सैकड़ों अनुयायी हताहत हो गए। भगवान बिरसा मुंडाजी ने देश-समाज के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जेल के अंदर रहस्यमय ढंग से उनकी मृत्यु हो गई।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2016 में देश के ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर से अपने भाषण में स्वतंत्रता संग्राम में भगवान बिरसा मुंडाजी की महती भूमिका को रेखांकित किया था। उन्होंने कहा था कि जनजातीय महापुरुषों की स्मृति में संग्रहालय हो, जिससे छात्र प्रेरणा लेकर राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ आगे बढ़ें।

और 15 नवंबर, 2021 को यह अवसर आया जब उनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। जिस जेल में उनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हुई, वहां पर भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय का भी उद्घाटन हुआ। आज देश का जनजाति समाज गर्व के साथ प्रफुल्लित है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त कर रहा है।

अनुसूचित जनजाति समाज के हित में मोदी सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं?

सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अनुसूचित जनजाति के हित में सोचते हैं और उसे साकार करते हैं। जनजाति समाज आगे बढ़े, इस दृष्टि से मोदीजी को लगा कि सबसे पहले इनकी शिक्षा ठीक ढंग से हो, इसलिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंसियल स्कूल योजना बनाई और आज साढ़े सात सौ के आसपास ये विद्यालय बनने प्रारंभ हो गए हैं।

देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातियों के हित में सोचा। इसलिए, अलग से जनजातीय मंत्रालय का गठन किया। उस काम को प्रधानमंत्री मोदीजी तेजी से आगे ले गए।

जनजाति का जीवन जल, जंगल, जमीन से जुड़ा हुआ है। अंग्रेज

सरकार आई, उस समय 1927 में फॉरेस्ट एक्ट बना दिया, उसके बाद 1960 में एक्ट बना। 1980 में वन का राष्ट्रीयकरण किया गया। 2006 में कांग्रेस सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट बनाया। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट; विलेज फॉरेस्ट ऐसा वर्गीकरण कर दिया। इन सबके चलते जनजाति अपने अधिकार से वंचित होते गए। हमारे देश के प्रधानमंत्रीजी ने इन सारी चीजों को देखा और सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया कि उनका अधिकार कैसे प्राप्त हो। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कहा कि इसका सरलीकरण किया जाए। लोग अपने गांव की सीमा के अंदर अपनी वनभूमि पर उत्पादन कर सके और सामुदायिक वन का संरक्षण-संवर्धन कर सके, इसके साथ-साथ वहां से प्राप्त चीजों का विपणन भी कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए ज्वाइंट रिज्यॉल्यूशन करने का काम पिछले 6 जुलाई को हुआ है। इसके आधार पर देश भर के फॉरेस्ट विलेज और इसके निकट रहनेवाले लोग सामुदायिक वनाधिकार का लाभ लेने की योजना में आगे बढ़ रहे हैं। गांव-गांव में लोग समूह बनाकर वनधन केंद्र के माध्यम से वनोत्पाद को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्राइफेड के माध्यम से उसके विपणन के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए ट्राइबल फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से योजना बनाई गई है। मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग आदि विभागों में पचास प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर उनके रोजगार की व्यवस्था की गई है। स्टार्टअप योजना में इनके लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा आदिवासियों को गुमराह कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है?

कांग्रेस खुद दोषी है। संविधान निर्माण के समय से ही वह जनजातियों को धोखा देने का काम कर रही है। वह संविधान के अंदर जनजातियों की स्पष्ट परिभाषा तक नहीं बना पायी। अनुसूचित जाति को लेकर संविधान निर्माण के समय स्पष्ट रूप से कहा गया कि अनुसूचित जाति के जो लोग अपनी आस्था, विश्वास और पारम्परिक उपासना को अगर त्याग देते हैं, वह अनुसूचित जाति की सूची से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अनुसूचित जनजाति के लोग जिन्होंने आस्था, विश्वास और परंपरा; इन सारी चीजों को वर्षों-वर्षों से त्याग दिया है वे आज भी अनुसूचित जनजाति के रूप में बने हुए हैं। वर्तमान में 729 अनुसूचित जनजातियों की सूची है।

अनुसूचित जनजाति के लोग कहते हैं कि हम प्रकृति पूजक हैं। यानी सीधे सनातनी भाव के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वह सनातन हैं। लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने उनके बारे में देश भर में भ्रम फैलाया कि वे सनातनी नहीं हैं।

आजादी के बाद से चाहे केंद्र में हो या बाकी राज्यों में, अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें रही हैं लेकिन उन्हें अनुसूचित जनजाति हित में सोचने तक की फुर्सत नहीं रही। योजना बनाने का विषय तो बाद की है।

हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदीजी जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे अंतर्मन से काम कर रहे हैं, यह कांग्रेस के लोगों को पच नहीं रहा है।

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की गतिविधियों के बारे में बताएं।

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद हमने संगठन की अंतिम इकाई 'बूथ' के कार्यकर्ताओं तक पहुंच बनाई है। मोर्चा जनजाति समाज में पार्टी की विचारधारा का प्रसार कर रहा है। अभी लगभग 30 संगठनात्मक प्रदेशों में हम काम कर रहे हैं। उसमें से 20 प्रदेशों में मेरे स्वयं का प्रवास हो चुका है। हमारे पदाधिकारीगण भी प्रवास कर रहे हैं। इससे हमारी संगठनात्मक संरचना नीचे स्तर तक ठीक ढंग से बन रही है। गत 22, 23 और 24 अक्टूबर को एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारणी बैठक रांची में संपन्न हुई। उसमें सभी प्रदेशों से जो अपेक्षित थे उतने लोग आए। इस महामारी के समय में भी एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 'सेवा ही संगठन', 'सेवा समर्पण अभियान' जैसे रचनात्मक अभियानों में पूर्ण मनोयोग के साथ महती भूमिका निभाई है।

भाजपा के प्रति जनजाति समाज का समर्थन निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान में आरक्षित और अनारक्षित सीटों को मिलाकर पार्टी के 40 लोकसभा सांसद हैं और राज्यसभा में 7 सांसद। प्रधानमंत्री मोदीजी भी पूरे विश्वास के साथ जनजातियों के हित में काम कर रहे हैं। इसीलिए नारा है— सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उनकी यात्रा में जनजाति समाज और मोर्चा के कार्यकर्ता भी सहयोग करते आगे बढ़ रहे हैं।

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की आगामी योजनाएं क्या हैं?

अनुसूचित जनजाति समाज की प्रमुख समस्याएं हैं— पलायन और बेरोजगारी। इसे दूर करने के लिए हम पहल कर रहे हैं। संसदीय संकुल विकास योजना बनाने को लेकर कार्य चल रहा है। अभी तक हम लोग ऐसे 40 संसदीय क्षेत्रों को एक कलस्टर के रूप में चयनित कर चुके हैं। कलस्टर के अंदर गांव भी चयनित हो गए हैं। इस संबंध में हमारी दो तीन स्तर की बैठकें और कार्यशाला भी हो गई हैं। वहां क्या-क्या संभावनाएं हैं, इन सारी चीजों का सर्वेक्षण कर सूचीबद्ध कर लिया गया है। अब हम वहां कैसे एक साल के भीतर उसी परिसर के अंदर उन लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कैसे पलायन को रोक सकते हैं, वहां की उत्पादित चीजों का प्रसंस्करण करते हुए किस प्रकार से बाजार तक पहुंचा सकते हैं, उनकी आमदनी कैसे सीधे उनकी जेब में आ सकती है, इस प्रकार से योजना करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ताकि 'आत्मनिर्भर भारत' की जो परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की है, वह साकार हो सके। ■

मोदी—एक करिश्माई संगठनकर्ता

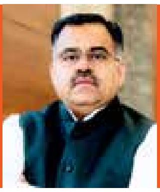

तरूण चुग
राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा

प्रसिद्ध समाजशास्त्री वेबर ने सत्ता का एक वर्गीकरण दिया है, जिसे उन्होंने तीन प्रकारों में विभाजित किया हैः पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी-तर्कसंगत सत्ता। पारंपरिक अधिकार रखने वाला नेता सत्ता में इसलिए आता है, क्योंकि उसके परिवार या कबीले ने हमेशा समूह का नेतृत्व प्रदान किया है। दूसरे प्रकार का अधिकार कानूनी तर्कसंगत प्राधिकरण है, जो तर्कसंगत सामाजिक क्रिया पर आधारित एक प्राधिकरण है। प्राधिकरण का सबसे दिलचस्प और प्रचलित प्रकार करिश्माई अधिकार है, जो उस व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों का परिणाम है जो इसका प्रयोग करता है। करिश्माई नेतृत्व एक शक्तिशाली व्यक्तिगत गुण है जो लोगों को आकर्षित और प्रभावित करता है। यह भावात्मक सामाजिक क्रिया से मेल खाती है। वेबर के लिए, करिश्माई व्यक्तित्व एक क्रांतिकारी शक्ति थी, जो नेता के व्यक्तिगत गुणों के माध्यम से समाज में व्यापक परिवर्तन ला सकती है। एक करिश्माई नेता का उदय मौजूदा व्यवस्था में सुधार ला सकता है और वर्तमान प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव ला सकता है। करिश्माई व्यक्तित्व के आधार पर कोई व्यक्ति सामान्य पुरुषों से अलग किया जाता है और अलौकिक या कम से कम विशेष रूप से असाधारण शक्तियों या गुणों से संपन्न माना जाता है, जिन्हें अनुकरणीय भी माना जाता है और उनके आधार पर संबंधित व्यक्ति को एक नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है। संकट और उथल-पुथल के समय में इस प्रकार का अधिकार अधिक स्पष्ट हो जाता है जब अन्य प्रकार की सत्ता विफल होने लगती हैं और सत्ता के नए रूपों की आवश्यकता होती है। जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति एक करिश्माई संगठनकर्ता है, तो इसका मतलब है कि वह व्यवस्थित और संगठित तरीके से सबसे अच्छा काम करता है। एक मास्टर-संगठनकर्ता के अन्य गुण हैंः

- वे उद्देश्य को निर्धारित करते हैं।
- वे समस्या को रचनात्मक तरीके से हल करते हैं।
- वे रिश्ते बनाने में विश्वास करते हैं।
- वे सीमित संसाधनों के साथ रणनीतिक रूप से कार्य करना जानते हैं।
- उनका व्यक्तित्व ईमानदार एवं पारदर्शी होता है।

> **एक संगठनकर्ता के रूप में मोदी जी का करिश्मा रातों रात नहीं हो गया। उन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली, फिर भी दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता के रूप में वे स्थापित हुए**

- वे अपने दृष्टिकोण को जनसामान्य को सरलता से बताते हैं।
- वे अपनी व्यक्तिगत हित से पहले समूह के हितों को देखते हैं।

पिछले दशकों में हमने भारत के राजनीतिक क्षेत्र में एक करिश्माई संगठनकर्ता का उदय देखा है। एक बहुत ही विनम्र पृष्ठभूमि से एक नया करिश्माई और जन-अनुसरण करने वाला व्यक्ति उभरा, जो राष्ट्र के भविष्य के पाठ्यक्रम की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक संगठनकर्ता के रूप में मोदी जी का करिश्मा रातों-रात नहीं हो गया। उन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली, फिर भी दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता के रूप में वे स्थापित हुए।

आइए देखें कि उनमें कौन से गुण हैं, जिन्होंने उन्हें सबसे करिश्माई संगठनकर्ता बना दिया है।

एक स्वीकार्य संगठनकर्ता की सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक यह है कि वह हमेशा 'मिशन' से प्रेरित होता है चाहे वह व्यक्तिगत जीवन का मिशन हो या सामाजिक मिशन। मोदी जी का देश की सेवा करने का एक व्यक्तिगत मिशन और भारत को दुनिया का सबसे विकसित देश बनाने का एक सामाजिक मिशन है। इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। 17 साल की उम्र में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा करने के लिए घर छोड़ दिया। दो वर्षों तक उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों, क्षेत्रों और लोगों की खोज करते हुए भारत के विस्तृत परिदृश्य की यात्रा की। जब वह घर लौटे तो वे एक बदला हुआ आदमी बन चुके थे, जिसका स्पष्ट उद्देश्य था कि वह जीवन में क्या हासिल करना चाहता है। आरएसएस के प्रचारक के रूप में और फिर आरएसएस में विभिन्न कार्यकर्त्ता के रूप में, उन्होंने एक मिशन-संचालित, निःस्वार्थ और सामाजिक लक्ष्य उन्मुख आयोजक होने की अपनी क्षमता को साबित किया है।

नेताओं की कुछ आदतें होती हैं, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। वर्ष 1972 के बाद से ही उन्होंने अहमदाबाद में बहुत कठिन दिनचर्या का पालन किया। जब वे आरएसएस के प्रचारक बने, उनका दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात तक चलता था। वर्ष 1980 के दशक के दौरान संघ के भीतर विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाते हुए नरेन्द्र मोदी अपने संगठनकर्ता कौशल के साथ एक संगठनकर्ता के उदाहरण के रूप में उभरे। संगठनकर्ता समस्या देखता है और उसका समाधान ढूंढ़ता है और हर स्थिति में चाहे वह समस्या हो या चुनौती। उन्होंने अपने निजी जीवन में अतिसूक्ष्मवाद के दर्शन को जीया है। चूंकि, एक संगठनकर्ता समाधान ढूंढ़ता है, उसके लिए मौजूदा संसाधनों के साथ

सबसे अच्छा काम करना होता है।

वर्ष 1987 में उन्हें गुजरात भाजपा का महामंत्री बनाया गया था। अपने पहले कार्य में ही मोदी जी ने पहली बार अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा के लिए जीत हासिल की। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि वर्ष 1990 के गुजरात विधानसभा चुनावों में भाजपा कांग्रेस के करीब पहुंच गई थी। वर्ष 1995 के विधानसभा चुनावों में यह उनकी संगठनात्मक कुशाग्रता थी जिसने सुनिश्चित किया कि भाजपा के वोट शेयर में भारी वृद्धि हुई और पार्टी ने विधानसभा में 121 सीटें जीतीं। श्री मोदी ने वर्ष 1995 से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पार्टी की गतिविधियों को देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री के रूप में काम किया। भाजपा के महामंत्री के रूप में उन्होंने वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम किया। सितंबर, 2001 में वह संगठन के निर्देशानुसार राजनीतिक प्रशासन के क्षेत्र में प्रवेश किया।

एक संगठनकर्ता के रूप में मोदी जी का संबंध भारत के राजनीतिक स्पेक्ट्रम से बहुत आगे तक फैला हुआ है और उन्होंने दुनिया भर के लोगों और नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित किया है। जब ईमानदारी इन दिनों विशेष रूप से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है, तो मोदी जी इसके आदर्श उदाहरण हैं। मोदी जी ने अब तक सार्वजनिक जीवन में लगभग 20 वर्षों तक शासन में सेवा की है, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। भारत के इस विशिष्ट कार्यकारी व्यक्तित्व द्वारा आत्मसात किए गए व्यक्तिगत त्रुटिहीन चरित्र और संस्कारों (मूल्यों) के कारण उनके खिलाफ व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन में किसी भी गलत काम का एक भी आरोप नहीं लगाया गया है। वह हाल के दिनों में हमारे द्वारा अनुभव किये गए ऐसे विशिष्ट वक्ता हैं, जो जनता की नब्ज और दर्द को जानकर जनता से जुड़ सकते हैं, जो अपने सरल लेकिन प्रभावी संचार-कौशल से अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। एक शिल्पकार-संगठनकर्ता के लिए 'पूर्ण' हमेशा 'भाग' से बड़ा होता है। उनके लिए राजनीति सत्ता पाने के लिए नहीं है बल्कि राजनीति राष्ट्र सेवा के लिए है। उन्होंने भौतिक जीवन के अपने सभी भोगों को राष्ट्र और पार्टी की सेवा करने के उद्देश्य से त्याग दिया है, जिसे वे अपना परिवार कहते हैं। ऐसे महामानव का भारत का राजनीतिक शिखर पर विद्यमान होना बड़े सौभाग्य की बात है। ■

पिछले तीन वर्षों में 57 लाख में से 54 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान; राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में ऑनलाइन केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर दायर की गई जन शिकायतों की कुल संख्या 57,25,443 है, जिसमें 54,65,826 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

दो दिसंबर को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉ. सिंह ने बताया कि कुछ सामान्य शिकायत श्रेणियां भ्रष्टाचार/दुर्व्यवहार, भूमि संबंधी समस्याओं, पर्यावरण मुद्दों/पशु कल्याण/वन संरक्षण, उत्पीड़न/अत्याचार, पुलिस, रेलवे आदि हैं।

सितंबर, 2019 से 14 शीर्ष शिकायत प्राप्त करने वाले मंत्रालयों में लागू सीपीजीआरएएमएस संस्करण 7.0 के तहत मंत्रालय विशिष्ट शिकायत श्रेणियां पेश की गई हैं, ताकि नागरिक उस श्रेणी और उप श्रेणी का चयन कर सकें जिसमें शिकायत दर्ज की जानी है। सीपीजीआरएएमएस नागरिक को उसकी शिकायत के निपटारे के बाद फीडबैक विकल्प प्रदान करता है। यदि नागरिक संकल्प से संतुष्ट नहीं है और निपटान को 'खराब' के रूप में रेट करता है, तो अगले उच्च प्राधिकारी को अपील दायर करने का विकल्प सीपीजीआरएएमएस में सक्षम है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 4,90,044 नागरिकों ने फीडबैक दिया और 66,396 अपीलें दायर की गईं, जिनमें से 52,242 अपीलों का निपटारा किया जा चुका है। ■

'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना'

दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम

राम प्रसाद त्रिपाठी

दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई)' ने कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की है। कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रकोप के कारण देशव्यापी तालाबंदी के मद्देनजर भारत सरकार ने मार्च 2020 में नियमित मासिक खाद्य आपूर्ति के अलावा लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न के वितरण की घोषणा की थी। इस अतिरिक्त खाद्यान्न की व्यवस्था इसलिए की गयी थी ताकि गरीब, जरूरतमंद और कमजोर परिवारों को देशव्यापी तालाबंदी और आर्थिक परेशानियों का सामना करने में सुगमता हो।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को मानवीय स्पर्श के साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए उनकी दूरदृष्टि, नवाचार और पथप्रदर्शक विचारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने 'आत्मनिर्भर भारत' योजना के तहत कोविड महामारी के प्रकोप के बीच गरीबों और कमजोरों को बचाने के लिए इस महामारी के प्रारंभिक चरण में पीएम-जीकेएवाई योजना शुरू करके एक बार फिर इसे साबित किया। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो चावल/गेहूं और 1 किलो मुफ्त दाल प्रदान की गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीएम-जीकेएवाई योजना ने महामारी के दौरान भारत के लगभग 81.35 करोड़ जरूरतमंद और सबसे गरीब लोगों को लाभ पहुंचाया है।

आज देश मोदी सरकार के मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के साथ आगे बढ़ रहा है, जो अंत्योदय के सिद्धांत या शासन की मूल भावना के रूप में अंतिम व्यक्ति के उत्थान द्वारा निर्देशित है। इस सिद्धांत को चरित्रार्थ करते हुए सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और ऐसे परिवारों जिनकों विधवाओं या मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों, विकलांग व्यक्तियों या 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है, उनको योजना के लाभार्थियों के रूप में शामिल किया है। सभी आदिवासी परिवार, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति भी इस योजना के हिस्सा रहे।

कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रकोप के कारण देशव्यापी तालाबंदी के मद्देनजर भारत सरकार ने मार्च 2020 में नियमित मासिक खाद्य आपूर्ति के अलावा लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न के वितरण की घोषणा की थी। इस अतिरिक्त खाद्यान्न की व्यवस्था इसलिए की गयी थी ताकि गरीब, जरूरतमंद और कमजोर परिवारों को देशव्यापी तालाबंदी और आर्थिक परेशानियों का समाना करने में सुगमता हो

यह योजना शुरू में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा मौजूदा 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना' के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी और इसे अप्रैल से जून, 2020 की अवधि के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये की लागत से शुरु किया गया था। इस कल्याणकारी योजना के तहत मई, 2020 के अंत तक खाद्य मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक 740 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिला और इसने देश में व्यापक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है।

इस योजना की सफलता से उत्साहित प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसको नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया, जिसके लिए 90,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और 80 करोड़ लोगों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना का पहला चरण अप्रैल से जून, 2020, दूसरा चरण क्रमशः जुलाई से नवंबर, 2020, तीसरा चरण मई से जून, 2021 तक और चौथा चरण जुलाई से नवंबर, 2021 तक लागू किया गया। पीएम-जीकेएवाई चरण एक से चार के तहत भारत सरकार ने कुल 600 एलएमटी खाद्यान्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को आवंटित किया, जो लगभग 2.07 लाख करोड़ रुपये खाद्य सब्सिडी के बराबर है। रिपोर्ट के अनुसार, पीएम-जीकेएवाई-IV के तहत कुल 93.8 प्रतिशत खाद्यान्न ले लिया गया है और क्रमशः लगभग 74.64 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किया गया है।

हाल ही में प्रधानमंत्री ने 53344.52 करोड़ रुपये की अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी

शेष पृष्ठ 30 पर...

'पीएम-कुसुम' किसानों की आय दोगुनी व कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायक

विकास आनंद

भारत ने नवंबर माह में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% स्थापित बिजली क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया। जलवायु परिवर्तन पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित 21वें सम्मेलन (सीओपी) में भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई थी। लेकिन मोदी सरकार की लक्ष्य के प्रति समर्पण ने 2030 के निर्धारित समय से सात साल पहले ही 40% लक्ष्य हासिल कर लिया। देश की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता आज 150.05 गीगावॉट है, जबकि इसकी परमाणु ऊर्जा आधारित स्थापित बिजली क्षमता 6.78 गीगावॉट है। यह कुल गैर-जीवाश्म-आधारित स्थापित ऊर्जा क्षमता को 156.83 GW तक लाता है, जो कि 390.8 GW की कुल स्थापित बिजली क्षमता का 40.1% है। हाल ही में संपन्न COP26 में प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुरूप सरकार वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 GW स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हो रही है।

पिछले 7 वर्षों में सौर क्षमता लगभग 2.6 GW से बढ़कर 42 GW से अधिक हो गई है। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2019 के बीच करीब 19 गुना ज्यादा सोलर पंप लगाए गए। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसने देश में सोलर क्षमता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन विभिन्न योजनाओं में पीएम-कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान) उस दिशा में महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसे फरवरी 2019 में मोदी सरकार द्वारा शुरु की गयी और इसका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है।

मुख्य विशेषता

'पीएम-कुसुम योजना' ग्रामीण क्षेत्रों में 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को सहायता प्रदान करती है; बिना ग्रिड से जुड़े स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सौर जल पंपों की स्थापना में सहायता और किसानों को ग्रिड आपूर्ति से स्वतंत्र बनाने के लिए मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरकरण और उन्हें अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पादन को बिजली वितरण कंपनी को बेचने में सक्षम बनाता है जिससे उन्हें अतिरिक्त आय अर्जित हो। इस योजना के तहत सौर पंपों और पैनलों की स्थापना के लिए चयनित विक्रेताओं को पंप के चालू होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए मरम्मत और रखरखाव प्रदान करना आवश्यक होता है। प्रत्येक परिचालन जिले में उनका एक अधिकृत सेवा केंद्र होगा और प्रत्येक परिचालन राज्य में स्थानीय भाषा में एक हेल्पलाइन होगी। यह किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करेगा और उनकी आय में वृद्धि करेगा, कृषि क्षेत्र का डीजल पर निर्भरता कम करेगा और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने मे भी सहायक होग। पीएम-कुसुम योजना पारेषण (transmission) लाइनों की उच्च लागत और नुकसान से भी बचाएगी। किसानों को आमतौर पर रात में सिंचाई के लिए बिजली मिलती है। इससे न केवल उन्हें काफी असुविधा होती है, बल्कि पानी की बर्बादी भी होती है क्योंकि एक बार चालू होने के बाद पंप चालू रह जाते हैं। PM-KUSUM के तहत सिंचाई के लिए सौर पैनल प्रदान करने से किसानों को दिन के समय भी बिजली मिलेगी, जिससे उनके लिए सिंचाई आसान हो जाएगी और पानी और बिजली के अधिक उपयोग से भी बचा जा सकेगा।

संचालन तंत्र

इस तरह पीएम कुसुम योजना के संचालन के तीन मुख्य तंत्र

हैंः 1. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, प्रत्येक की क्षमता 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक; 2. जो किसान ग्रिड से जुड़े नहीं हैं, उनकी सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग ऑफ-ग्रिड सौर जल पंपों की स्थापना और 3. किसानों को ग्रिड आपूर्ति से स्वतंत्र करने के लिए मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरकरण और उन्हें उत्पन्न अधिशेष सौर ऊर्जा DISCOM को बेचने की अनुमति देना जिससे अतिरिक्त आय अर्जित कर सके। इसके तहत बंजर/परती/दलदली/चारागाह या खेती योग्य भूमि पर व्यक्तिगत रुप से /सहकारिता/पंचायतों/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) द्वारा 2MW तक क्षमता के छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। यदि खेती वाले क्षेत्रों को सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए चुना जाता है, तो सौर संयंत्रों से उत्पन्न बिजली को वितरण कंपनियों (DISCOMs) द्वारा संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERCs) द्वारा निर्धारित टैरिफ पर खरीदा जाने का प्रावधान है।

निष्कर्ष

किसानों की आय दोगुनी करने और उनके रहन-सहन की स्थिति में सुधार के अलावा यह योजना पेट्रोलियम और कोयले के आयात पर बढ़ते खर्च को रोकने में भी बहुत मददगार होगी। पेट्रोलियम के आयात पर भारत का खर्च बहुत बड़ा है। यह लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते व्यापार घाटे में परिणत होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोयले की घरेलू कमी के कारण इस साल नवंबर में कुल 23.3 अरब डॉलर के व्यापार घाटे में से 3.6 अरब डॉलर कोयले का आयात हुआ। कोयले का उपयोग ज्यादातर बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। 'पीएम-कुसुम' जैसी योजनाओं से कोयला ऊर्जा पर हमारी निर्भरता कम होगी और हमारे व्यापार घाटे को भी कम करने में मदद मिलेगी, जबकि नवंबर में पेट्रोलियम उत्पाद आयात की लागत 14.6 अरब डॉलर थी। पीएम-कुसुम के तहत मौजूदा डीजल पंपों को सौर पंपों से बदलने से न केवल सिंचाई लागत और आयात पर भारत के खर्च में कमी आएगी, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। ■

पृष्ठ १8 का शेष...

के साथ, दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक पीएम—जीकेएवाई के पांचवें चरण की घोषणा की। पीएमजीकेएवाई चरण-V के लिए कुल 163 एलएमटी खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। पहले के चरणों के अनुरुप पीएम—जीकेएवाई-V का प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है। सरकार पीएम-जीकेएवाई के चरण I से V तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।

मोदी सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों तक पहुंचे। सरकार की इस योजना के साथ भारत दुनिया का एकमात्र देश बन गया है जो बिना किसी भेदभाव के 24 महीने के लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान कर रहा है। इस उदार नजरिये और इसके जबरदस्त परिणाम के कारण पूरी दुनिया ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के लाभों को स्वीकार किया है।

इस योजना की सराहना करते हुए डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने कहा, "पीएम मोदी ने न केवल स्वास्थ्य के मुद्दों को हल किया है, बल्कि आर्थिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया है और इसे अन्य देशों द्वारा दोहराया जाना चाहिए।"

सार्वभौमिक पीएम-जीकेएवाई योजना की सराहना करते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, ''भारत ने दो कदम उठाए हैं- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्म निर्भर भारत- जो देश के आर्थिक मुद्दों का ख्याल रख रहे हैं और यह सराहनीय है।"

निस्संदेह, पिछली सदी के दौरान पूरी दुनिया के सामने कोविड-19 महामारी एक बड़ा संकट था और आज भी है, जिसने दुनिया के सबसे उन्नत देशों को भी नहीं बख्शा। पिछले अनुभव बताते हैं, जब भी कोई बड़ी त्रासदी इतनी बड़ी आबादी पर आती है, तो इससे समाज में अस्थिरता पैदा होती है। हालांकि, प्रधानमंत्री श्री मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो किया उसने सभी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। ऐसे कठिन समय में भी भारत ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि एक भी गरीब व्यक्ति भूखा न रहे। इसके अतिरिक्त, भारत ने महामारी के दौरान गरीब, असहाय, बुजुर्ग लोगों को सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता भी प्रदान की। प्रवासी श्रमिकों के लिए 'वन नेशन वन राशन कार्ड' की सुविधा शुरू की गई, ताकि यह प्रवासी देश में कहीं भी रहें, उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मानवीय, संवेदनशीलता को सर्वोपरि रखते हुए गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सभी को साथ लेकर चलने के पीएम श्री मोदी के प्रयासों ने निश्चित रूप से इस कठिन समय में देश के गरीब, जरूरतमंद, छोटे किसानों और छोटे व्यापारियों को बहुत ताकत दी है। पिछले दो वर्षों में वितरित इस मुफ्त राशन ने यह निश्चित किया कि महामारी के इस दौर में गरीबों पर आने वाले संकट को कम किया जा सके और उनके जीवन और आजीविका में सहयोग किया जा सके। जनता का विश्वास प्रधानमंत्री श्री मोदी के शासन की आधारशिला है जो एक 'नए भारत' की परिकल्पना को आगे बढ़ाता है और एक ऐसा भारत का निर्माण के लिए रास्ता प्रशस्त करता है जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से कहीं अधिक दृढ़ और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। ■

भारत और रूस 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्' सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने पर हुए सहमत

रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए छह दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली का दौरा किया। राष्ट्रपति श्री पुतिन के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया था। प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रपति श्री पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण माहौल में हुई। दोनों नेताओं ने कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' में निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

उन्होंने छह दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता की पहली बैठक और सैन्य एवं सैन्य-तकनीकी सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग की बैठक का स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया और इस संदर्भ में दीर्घकालिक पूर्वानुमान योग्य और सतत आर्थिक सहयोग के लिए विकास के नए कारकों पर जोर दिया। उन्होंने परस्पर निवेश की सफलता की कहानी की सराहना की और एक दूसरे के देशों में अधिक से अधिक निवेश की उम्मीद जताई।

दोनों नेताओं के बीच इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) और प्रस्तावित चेन्नई-व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्टिविटी की भूमिका पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत के राज्यों के साथ रूस के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से रूसी सुदूर-पूर्व के साथ पहले से अधिक अंतर-क्षेत्रीय सहयोग की उम्मीद जताई। उन्होंने कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष में चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की सराहना की। इसमें दोनों देशों द्वारा जरूरत के इस संकट काल में एक दूसरे को मानवीय सहायता प्रदान करना भी शामिल है।

दोनों नेताओं ने कोविड महामारी के बाद वैश्विक आर्थिक सुधार और अफगानिस्तान की स्थिति सहित क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर चर्चा की। वे इस बात पर सहमत हुए कि अफगानिस्तान को लेकर दोनों देशों के समान दृष्टिकोण और चिंताएं हैं और अफगानिस्तान पर परामर्श और सहयोग के लिए एनएसए स्तर पर तैयार किए गए द्विपक्षीय रोडमैप की दोनों सराहना करते हैं।

उन्होंने इस बात पर गौर किया कि दोनों पक्षों ने कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर समान दृष्टिकोण साझा किए हैं और वे 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्' सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति श्री पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की चल रही अस्थायी सदस्यता और 2021 में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी आर्कटिक परिषद् की वर्तमान अध्यक्षता के लिए रूस को बधाई दी।

'भारत-रूसः शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी' शीर्षक वाले संयुक्त वक्तव्य में राज्य और द्विपक्षीय संबंधों की संभावनाओं को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। इस यात्रा के साथ-साथ व्यापार, ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा, बाहरी अंतरिक्ष, भूगर्भीय खोज, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शिक्षा इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दोनों सरकारों के बीच कई समझौतों और समझौता ज्ञापनों के साथ-साथ दोनों देशों के वाणिज्यिक और अन्य संगठनों के बीच भी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यह हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की बहुआयामी प्रकृति का एक प्रतिबिंब है।

राष्ट्रपति श्री पुतिन ने 2022 में 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को रूस आने का निमंत्रण दिया। ■

भारत-रूस ने 2025 तक आपसी व्यापार 30 अरब डॉलर और निवेश 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा: नरेन्द्र मोदी

21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छह दिसंबर को कहा कि पिछले कुछ दशकों में कई बुनियादी चीजें बदली हैं और नए भू-राजनैतिक दृष्टिकोण सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बदलावों के बावजूद भारत-रूस मैत्री कायम है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद की है और एक दूसरे की संवेदनशीलता का भी ध्यान रखा है।

उन्होंने कहा कि वे आर्थिक मामलों में द्विपक्षीय साझेदारी को सुदृढ करने के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने 2025 तक 30 बिलियन डॉलर के व्यापार और 50 बिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा है।

'मोदी 2.0 ए रिजॉल्व टू सिक्योर इंडिया' पुस्तक का लोकार्पण

'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमें गौरवान्वित किया'

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष ने 02 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 'मोदी 2.0 ए रिजॉल्व टू सिक्योर इंडिया' पुस्तक का लोकार्पण किया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन ने पेंटागन प्रेस के सहयोग से इस नवीनतम अंक को प्रकाशित किया है, इस अंक में इस बात पर चर्चा की गयी है कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक नए दृष्टिकोण देने के साथ ही इसे व्यापक रूप से बदल दिया है।

इस अवसर पर प्रो. बिबेक देबरॉय, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद, श्री रंजीत पंचंदा, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के पूर्व महानिदेशक, डॉ. उत्तम सिन्हा, फेलो, मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान उपस्थित थे। इसके अलावा डॉ. अनिर्बान गांगुली, निदेशक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन और श्री राजन आर्य, प्रबंध निदेशक, पेंटागन प्रेस भी उपस्थित थे।

पुस्तक के विमोचन के अवसर पर श्री बीएल संतोष ने कहा कि इस पुस्तक को जो चीज विशिष्ट बनाती है, वह इसके लेखक और संपादक हैं। आधुनिक समय में विश्वास की भावना कम होती जा रही थी, लेकिन ये 7 साल नेतृत्व और व्यवस्था में विश्वास की भावना लेकर आए हैं। मोदी सरकार के 7 साल में जो कार्यक्षमता दिखी है, वह अन्य दलों की सरकारों में नहीं दिखी।

"आज मुझे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शब्द याद आ रहे हैं– "मुझे नहीं पता कि मैं अगले 5 वर्षों में क्या हासिल कर सकता हूं या क्या करूंगा, क्योंकि उपलब्धियां हासिल करने के लिए विभिन्न लोगों के समर्थन और प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं इस तरह से काम करूंगा कि अगली बार वोट मांगते समय आप में से किसी को भी अपना सिर नहीं झुकाना पड़े। श्री संतोष ने कहा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हमें गौरवान्वित किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीय हों, वे भारतीय हैं। हम एक ऐसी स्थिति का निर्माण करेंगे, जहां वे सभी अपने को भारतीय कहने में गर्व महसूस करेंगे।

प्रो. बिबेक देबरॉय ने कहा, "एक मजबूत और आक्रामक रक्षा रणनीति भारत के सुधार एजेंडे का एक अत्यंत आवश्यक हिस्सा है। हमारी सीमाओं पर उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए रणनीतियां और पुलिस सुधार विकास की गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।"

श्री रंजीत पंचंदा ने कहा, "मोदी सरकार प्रत्येक नागरिक, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में समान हितधारक है, को बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के खतरों से सुरक्षित रखने में विश्वास करती है।"

डॉ. अनिर्बान गांगुली ने कहा, मोदी सरकार में 'भारत एक नई सुरक्षा नजरिये की ठोस नींव पर खड़ा है जो एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा है।'

'मोदी 2.0 ए रिजॉल्व टू सिक्योर इंडिया' में मोदी सरकार के समग्र प्रदर्शन और रणनीतियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों और विचारशील नेताओं की उल्लेखनीय राय को शामिल किया गया है। यह खंड मोदी 2.0 सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर की गयी महत्वपूर्ण पहलों का एक व्यापक चित्रण प्रस्तुत करती है। ■

यूनिकॉर्न्स की दुनिया में भी भारत तेज उड़ान भर रहा है: नरेन्द्र मोदी

'यूनिकॉर्न' एक ऐसा स्टार्ट-अप होता है जिसका मूल्य कम से कम 1 अरब डॉलर होता है यानी करीब-करीब सात हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 28 नवंबर, 2021 को 'मन की बात' कार्यक्रम में दिए गए संबोधन के मुख्य अंश :

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 नवंबर को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 83वीं कड़ी में कहा कि दो दिन बाद दिसम्बर का महीना भी शुरू हो रहा है और दिसम्बर आते ही मनोवैज्ञानिक रूप से हमें ऐसा ही लगता है कि चलिए भई साल पूरा हो गया। ये साल का आखिरी महीना है और नए साल के लिए ताने-बाने बुनना शुरू कर देते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने नौसेना दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी देश मनाता है। हम सबको मालूम है 16 दिसम्बर को 1971 के युद्ध की स्वर्णिम जयन्ती वर्ष भी देश मना रहा है। मैं इन सभी अवसरों पर देश के सुरक्षा बलों का स्मरण करता हूं, हमारे वीरों का स्मरण करता हूं और विशेष रूप से ऐसे वीरों को जन्म देने वाली वीर माताओं का स्मरण करता हूं।

उन्होंने कहा कि दिसम्बर महीने में ही एक और बड़ा दिन हमारे सामने आता है जिससे हम प्रेरणा लेते हैं। ये दिन है, 6 दिसम्बर को बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिये अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये समर्पित किया था। हम देशवासी ये कभी न भूलें कि हमारे संविधान की भी मूल भावना, हमारा संविधान हम सभी देशवासियों से अपने-अपने कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा करता है— तो आइये, हम भी संकल्प लें कि अमृत महोत्सव में हम कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे। यही बाबा साहब के लिये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आजादी में अपने जनजातीय समुदाय के योगदान को देखते हुए देश ने जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया है। देश के अलग-अलग हिस्सों में इससे जुड़े कार्यक्रम भी हुए। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे, ऐसे जनजातीय समुदायों के लोगों ने अपनी संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन किया।

उन्होंने कहा कि युवाओं से समृद्ध हर देश में तीन चीजें बहुत मायने रखती हैं। अब वही तो कभी-कभी युवा की सच्ची पहचान बन जाती है। पहली चीज है– आइडियाज और इनोवेशन। दूसरी है– जोखिम लेने का जज्बा और तीसरी है– Can Do Spirit यानी किसी भी काम को पूरा करने की जिद्द, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों। जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो अभूतपूर्व परिणाम मिलते हैं। चमत्कार हो जाते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि आजकल हम चारों तरफ सुनते हैं स्टार्ट-अप, स्टार्ट-अप, स्टार्ट-अप। सही बात है, ये स्टार्ट-अप का युग है और ये भी सही है कि स्टार्ट-अप की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। साल-दर-साल स्टार्ट-अप को रिकॉर्ड निवेश मिल रहा है। ये क्षेत्र बहुत तेज रफ़्तार से आगे बढ़ रहा है। यहां तक कि देश के छोटे-छोटे शहरों में भी स्टार्ट-अप की पहुंच बढ़ी है। आज कल 'यूनिकॉर्न' शब्द खूब चर्चा में है। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। 'यूनिकॉर्न' एक ऐसा स्टार्ट-अप होता है जिसका मूल्य कम से कम 1 अरब डॉलर होता है यानी करीब-करीब सात हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा।

आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न्स

उन्होंने कहा कि साल 2015 तक देश में बमुश्किल नौ या दस यूनिकॉर्न्स हुआ करते थे। आपको ये जानकार बेहद ख़ुशी होगी कि अब यूनिकॉर्न्स की दुनिया में भी भारत तेज उड़ान भर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल एक बड़ा बदलाव आया है। सिर्फ 10 महीनों में ही भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बना है। ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे युवाओं ने ये सफलता कोरोना महामारी के बीच हासिल की है। आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं। यानी 70 से अधिक स्टार्ट-अप ऐसे हैं जो 1 अरब डॉलर से ज्यादा के मूल्य को पार कर गए हैं।

श्री मोदी ने कहा कि स्टार्ट-अप की सफलता के कारण हर किसी का उस पर ध्यान गया है और जिस प्रकार से देश से, विदेश से, निवेशकों से उसे समर्थन मिल रहा है। शायद कुछ साल पहले उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ■

भाजपा ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक संपन्न

भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 3 से 5 दिसंबर तक गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. के. लक्ष्मण ने की। बैठक को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बी.एल. संतोष एवं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और मोर्चा के पार्टी प्रभारी श्री अरुण सिंह ने संबोधित किया। बैठक में शामिल होने वालों में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल थे।

बैठक में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के हित में मोदी सरकार द्वारा की गई पहलों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री निखिल आनंद ने मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी।

इस बैठक के समापन सत्र में ओबीसी मोर्चा ने कोविड-19 महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को राहत देने के लिए 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' को मार्च 2022 तक बढ़ाने और भारत में निर्मित वैक्सीन के माध्यम से देश की पात्र आबादी का टीकाकरण करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। ■

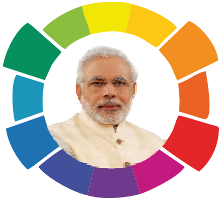

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

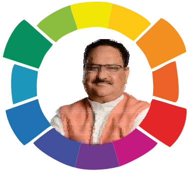

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)................................ (2)....................................

ईमेल : ....

सदस्यता	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :.................................... दिनांक :.............................. बैंक : ....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।

मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे। (हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

नई दिल्ली स्थित संसद भवन में संविधान दिवस (26 नवंबर) समारोह में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व अन्य गणमान्य व्यक्ति

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 और टीकाकरण से संबंधित स्थिति पर शीर्ष अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर (उत्तर प्रदेश) का शिलान्यास करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व अन्य गणमान्य व्यक्ति

देहरादून (उत्तराखंड) में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

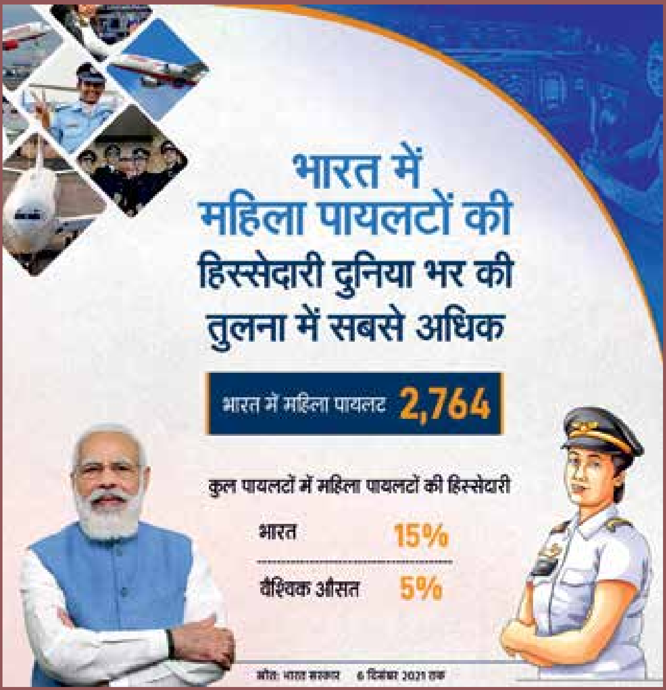

छायाकार: अजय कुमार सिंह